अगस्त 2021

मूल्य 20/-

सामाचार विश्लेषण की मासिक पत्रिका

जेट न्यूज

मोदी ने नहीं दिया नीतीश को भाव !

- मंत्रिमंडल विस्तार, एक पर भी खुश नीतीश!
- पुरानी डील पर माने नीतीश, मोदी ने नहीं बढ़ने दिया भाव
- केंद्रीय मंत्रिमंडल में हिस्सेदार पहली बार कोडरमा
- 2024 को साधने के लिए बंगाल से बनाये 4 नये मंत्री
- हेमंत सरकार गिराने पर रार, भाजपा-महागठबंधन में तकरार
- अंडर व्लर्ड क्वीन जेनाबाई के इशारों पर नाचते थे दाउद
- योगी की चुनावी बिसात पर विपक्षी मोहरों की चुनौती

24 JET NEWS.COM

Ranjeet Kumar
CEO & Director Editor Jet News

COMING SOON

Kolkata (W. B.)
Jharkhand, Bihar

संपादक
रंजीत कुमार

एसोसिएट एडिटर
विकास शर्मा

सहायक संपादक
रवि कुमार सिंह

दिल्ली ब्यूरो चीफ
आरके सिंह

पश्चिम बंगाल ब्यूरो चीफ
विश्वजीत घोष

झारखण्ड प्रतिनिधि
रिंकेश कुमार

बिहार प्रतिनिधि
मोहित कुमार

छायाकार
बिपिन बिहारी उपाध्याय

पेज डिजाईन
रवि रंजन गुप्ता

सलाहकार
सुभेंदु राय, अधिवक्ता (कोलकाता हाईकोर्ट)
तरुण गुबर, अधिवक्ता (दिल्ली हाईकोर्ट)

RNI. No. DELHIN/2015/63409

वर्ष - 07 अंक - 6 नई दिल्ली
अगस्त - 2021 मूल्य - 20 रुपये

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक रंजीत कुमार ने साईं प्रिंटर्स, न्यू अशोक नगर, दिल्ली-110095 से छपवाकर 2042, प्लॉट नं. जीए 33, राजदंगा मेन रोड, कोलकाता 700107 से प्रकाशित

ईमेल - ranjeetsingh0545@gmail.com

दिल्ली कार्यालय
109, एलआईजी फ्लैट, सरिता विहार, नई दिल्ली - 110076

अंदर के पन्नो पर

1. पेगासस का भंडाफोड़ बनाम एमनेस्टी से भारत सरकार का बदला 4-5
2. योगी की चुनावी बिसात पर विपक्षी मोहरों की चुनौती 6-7
3. 'बिहारी गुंडे' वाले बयान पर घिरीं टीएमसी सांसद 8
4. हेमंत सरकार गिराने पर रार भाजपा-महागठबंधन में तकरार 9
5 सरकार गिराने मामले की सीबीआई जांच के लिए याचिका 10
6. सीसीटीवी से खुले राज, दिखे 3 विधायक 11
7. सिद्धू के बढ़े कद और अमरिंदर के लिए संकेत 12
8. पुरानी डील पर माने नीतीश मोदी ने नहीं बढ़ने दिया भाव 13
9. मंत्रिमंडल विस्तार, एक पर भी खुश नीतीश! 14
10. केंद्रीय मंत्रिमंडल में हिस्सेदार पहली बार कोडरमा 15
11. 2024 को साधने के लिए बंगाल से बनाये 4 नये मंत्री 16
12. अंडर वर्ल्ड क्वीन जेनाबाई इशारों पर नाचते थे दाउद 17-18
13. बांग्लादेश : समुद्री पानी का कहर जिस्म बेचने को मजबूर औरतें 19
14. गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगौर गांधी के आलोचक भी मुरीद भी 20-21
15. आदिवासियों को चाहिए इन सवालों के जवाब 22-25
16. जदयू : नीतीश की नजर में आरसीपी सिंह बनाम उपेंद्र कुशवाहा 26
17. 15 अगस्त को आजाद हुआ पाकिस्तान 14 को क्यों मनाता है स्वतंत्रता दिवस? 27
18. राखी के जरिये एकजुट हुए हिंदू-मुसलमान माध्यम बने रवींद्रनाथ टैगोर 28-29
19. उच्च सदन में छिछालेदर संसद की गरिमा आहत 32
20. मीना कुमारी पर फिल्माए गए एक अमर गीत में वे होकर भी नहीं थीं! 33
21. श्रीदेवी संवेदनशील और खामोश अभिनेत्री 34

संपादकीय

पेगासस का भंडाफोड़ बनाम एमनेस्टी से भारत सरकार का बदला

मानव अधिकार के लिए लड़ने वाली संस्था 'एमनेस्टी इंटरनेशनल' अचानक एक जासूसी अभियान में कैसे शामिल हो गयी? उसने अपनी टेक्निकल लेबोरेट्री में स्पाईवेयर पेगासस की ओर से हैक किये नंबरों को कैसे एक्सेस कर लिया? पिछले साल भारत सरकार ने विदेशी चंदा मामले में गड़बड़ी करने के मामले में एमनेस्टी इंडिया की नकेल कसी थी। तो क्या भारत सरकार की कार्रवाई के खिलाफ पेगासस उसका जवाबी हमला है? 'नवभारत टाइम्स', 'हिन्दुस्तान' और 'दैनिक भास्कर' के संपादक रह चुके वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता ने वर्ष 1982 में भारत की प्रतिष्ठित पत्रिका दिनमान में एक आलेख लिखा था, जिसका शीर्षक था- 'क्या एमनेस्टी इंटरनेशनल गुप्तचर संस्था है?'

रंजीत कुमार
मुख्य संपादक और सीईओ
(जेट न्यूज व 24 जेट न्यूज डॉट कॉम)

मानवाधिकार पर काम करने वाले वैश्विक संस्था 'एमनेस्टी इंटरनेशनल' ब्रिटेन का बहुराष्ट्रीय एनजीओ है। लेकिन, क्या यह एक जासूसी है? यह सवाल आज पेगासस मामले के भंडाफोड़ के बाद उठना जरूरी भी है। भारत की प्रतिष्ठित राजनीतिक पत्रिका में 39 साल पहले एक चर्चित पत्रकार ने एक आलेख के जरिये भी यह सवाल उठाया था। तब न भाजपा की कोई अहमियत थी और न ही'देशभक्त' और'देशविरोधी' जैसे खांचों से लोग बंटे थे। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और इंदिरा गांधी ने दमदार तरीके से सत्ता में वापसी की थी। उस जमाने में अगर कोई एमनेस्टी इंटरनेशनल के खुफिया एंजेडे पर सवाल उठाता है तो इसपर आज के संदर्भ में भी गौर करना आवश्यक हो जाता है।

दरअसल, एमनेस्टी इंटरनेशनल का दावा है कि वह दुनिया भर में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए सक्रिय है। लेकिन, मानव अधिकार के लिए लड़ने वाली संस्था अचानक एक जासूसी अभियान में कैसे शामिल हो गयी? उसने अपनी टेक्निकल लेबोरेट्री में स्पाईवेयर पेगासस की ओर से हैक किये नंबरों को कैसे एक्सेस कर लिया? पिछले साल भारत सरकार ने विदेशी चंदा मामले में गड़बड़ी करने के मामले में एमनेस्टी इंडिया की नकेल कसी थी। तो क्या भारत सरकार की कार्रवाई के खिलाफ पेगासस उसका जवाबी हमला है?'नवभारत टाइम्स','हिन्दुस्तान' और'दैनिक भास्कर' के संपादक रह चुके वरिष्ठ पत्रकार आलोक मेहता ने वर्ष 1982 में भारत की प्रतिष्ठित पत्रिका दिनमान में एक आलेख लिखा था, जिसका शीर्षक था-'क्या एमनेस्टी इंटरनेशनल गुप्तचर संस्था है?'

यह लेख उस समय छपी थी जब'दिनमान' को सबसे निष्पक्ष और गंभीर पत्रिका माना जाता था। तब अंग्रेजी में यूपीएससी की तैयारी करने वाले छात्र जैसे'द हिंदू' अखबार पढ़ते थे उसी तरह हिंदी में प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र'दिनमान' पढ़ा करते थे। रघुवीर सहाय और अज्ञेय जैसे प्रकांड विद्वान'दिनमान' के संपादक हुए। उस समय दिनमान में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विषय पर छपने वाले आलेख उच्च कोटि के हुआ करते थे। यहां इन सब बातों का जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि'दिनमान' का प्रकाशन बहुत पहले बंद हो चुका है और आज की युवा पीढ़ी इसकी प्रतिष्ठा और ताकत से अंजान है।'दिनमान' में आलोक मेहता ने 1982 के में लिखे इस आलेख में कहा था कि कैसे भारत और तत्कालीन सोवियत संघ की सरकार ने एमनेस्टी इंटरनेशनल की गतिविधियों और फंडिंग पर गंभीर आरोप लगाये थे। एमनेस्टी इंटरनेशनल पर आरोप लगा था कि वह साम्राज्यवादी देशों की जासूसी संस्थाओं का एक हिस्सा है।

उल्लेखनीय है कि कई बार विदेशी जासूस अंडर कवर एजेंट के रूप में स्वयंसेवी संस्थाओं में काम करते हैं।

संपादकीय

एमनेस्टी इंटरनेशनल पर यह भी आरोप था कि वह ब्रिटिश जासूसी संस्था एमआइ6 के लिए भी काम करती है। एमनेस्टी भारत के घरेलू मामले में बहुत पहले से हस्तक्षेप कर रहा है। मानवाधिकार के नाम पर वह कभी कश्मीर, कभी दिल्ली दंगे तो कभी सीएए विरोध आंदोलन का मुद्दा उठाता रहा है। लेकिन, उसने कभी पाकिस्तान में गैरहिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और जेल में बंद राजनीतिक कैदियों पर जुल्म का मामला नहीं उठाया। इतना ही नहीं जब उत्तरी आयरलैंड में मानवाधिकार की धज्जियां उड़ती हैं तो एमनेस्टी खामोश हो जाता है। वर्ष 1972 में उत्तरी आयरलैंड के डेरी शहर में करीब 30 हजार लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, भीड़ अचानक बेकाबू हो गयी। तब ब्रिटिश सैनिकों ने उनपर गोलियां चला दीं जिसमें 13 आम लोग मारे गये थे। उत्तरी आयरलैंड में आज भी मानवाधिकार का घोर उल्लंघन हो रहा है, लेकिन एमनेस्टी इन मुद्दों को तूल नहीं देता है। यानी एमनेस्टी एक एजेंडा के तहत भारतीय मामलों में खास दिलचस्पी रखता है।

एमनेस्टी की भारत पर टिप्पणियों को बारीकी से देखें तो उसका भारत विरोधी नजरिया सामने आयेगा। केंद्र में जब यूपीए का शासन था तब भी एमनेस्टी को लेकर सरकार को परेशानी हुई थी। वर्ष 2011 की बात है। तमिलनाडु के तिरुनेलवेल्ली जिले के कुडनकुलम में 1000 मेगावाट के परमाणु बिजली संयंत्र पर काम चल रहा था। अचानक इस संयंत्र को असुरक्षित बता कर इसके निर्माण का विरोध किया जाने लगा। इसपर राजनीति भी शुरू हो गयी। पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल गोपाल कृष्ण गांधी परमाणु बिजली घर का विरोध करने लगे। दूसरी तरफ तत्कालीन राष्ट्रपति और महान वैज्ञानिक डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम ने संयंत्र के निर्माणस्थल का दौरा कर इसे सुरक्षित बताया था। लेकिन, उनकी बात को दरकिनार कर इस परमाणु बिजली घर के खिलाफ एक संगठित विरोध शुरू हो गया। इसमें ब्रिटेन के सांसद भी कूद पड़े।

ब्रिटेन के कुछ सांसदों ने कुडनकुलन परमाणु बिजली घर के विरोध में भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और तमिलनाडु की तत्कालीन मुख्यमंत्री जयललिता को एक पत्र लिख दिया। उन्होंने इस संयंत्र को बंद करने की मांग की। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है, इसलिए यह कहा जाने लगा कि विरोध की आग को वह भी हवा दे रहा है। उस समय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी कहा भी था कि परमाणु बिजली घर के खिलाफ विरोध आंदोलन में विदेशी ताकतों का हाथ है। अब पेगासस मामले का भंडाफोड़ कर एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भारत सरकार के सामने एक नया संकट खड़ा कर दिया है। ऐसे में एमनेस्टी के एक जासूसी संगठन के सवाल पर चर्चा शुरू की जानी जरूरी है।

योगी की चुनावी बिसात पर विपक्षी मोहरों की चुनौती

- चुनावी वर्ष में राज्य के सभी राजनीतिक दल अपनी-अपनी चुनावी बिसात बिछाने में तेजी से जुट गये हैं, जिसकी एक बहुत छोटी सी बानगी कुछ समय पूर्व संपन्न हुए पंचायत चुनाव व अभी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनावों में देखने को मिली है। हालांकि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनावों में कोई भी विपक्षी दल योगी आदित्यनाथ के चक्रव्यूह को भेदने में नाकाम रहा है। योगी ने राज्य में विधानसभा चुनावों से पूर्व हुई इस परीक्षा में अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करके 75 में 67 सीटों पर विजय हासिल करके एकजुट होने के प्रयास में लगे विपक्ष को अलग-अलग करके बिखर दिया है।

- उत्तर प्रदेश में अभी तक तो योगी आदित्यनाथ के व्यक्तित्व को सत्ता पक्ष व विपक्ष के किसी भी नेता से कोई बड़ी चुनौती नहीं मिल पा रही है। राज्य में विपक्ष बिखरा हुआ है इसका उदाहरण जिला पंचायत के चुनावों में जनता ने देख लिया है, वैसे भी राज्य में विपक्षी दलों के पास अखिलेश यादव, मायावती व प्रियंका गांधी के अलावा कोई ऐसा लोकप्रिय चेहरा नहीं है जो क्षेत्रीय क्षत्रप हो या लोकप्रिय जननेता हो। लेकिन इन सभी की कार्यशैली व लक्ष्य केवल मुस्लिम वोटों को आकर्षित करने का रहता है। जिसकी वजह से अन्य मतदाता इन से दूर हो जाता है जिसकी वजह से राज्य में भाजपा को विशेष सकारात्मक ऊर्जा मिलती है।

उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव वर्ष 2022 में तय समय पर ही होने की संभावना है। क्योंकि, कोरोना का कहर धीमा हुआ है। वर्ष 2017 में निर्वाचित वर्तमान राज्य विधानसभा का कार्यकाल 14 मई 2022 को समाप्त होगा, इसलिए चुनाव आयोग को राज्य में किसी भी तरह के संवैधानिक संकट से बचने के लिए उससे पहले चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराना होगा। सो, उम्मीद है कि राज्य में विधानसभा चुनावों की प्रक्रिया फरवरी या मार्च में हर हाल में शुरू होकर अपने तय समय से पहले पूर्ण हो जाएगी। चुनावी वर्ष में राज्य के सभी राजनीतिक दल अपनी-अपनी चुनावी बिसात बिछाने में तेजी से जुट गये हैं, जिसकी एक बहुत छोटी सी बानगी कुछ समय पूर्व संपन्न हुए पंचायत चुनाव व अभी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनावों में देखने को मिली है। हालांकि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनावों में कोई भी विपक्षी दल योगी आदित्यनाथ के चक्रव्यूह को भेदने में नाकाम रहा है। योगी ने राज्य में विधानसभा चुनावों से पूर्व हुई इस परीक्षा में अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करके 75 में 67 सीटों पर विजय हासिल करके एकजुट होने के प्रयास में लगे विपक्ष को अलग-अलग करके बिखर दिया है। जीत हासिल करने के लिए जिला पंचायत चुनावों में बेशक सिस्टम का जमकर दुरूपयोग होता हो, लेकिन ऐसा पहली बार नहीं हो रहा हर राजनीतिक दल ने अपने राज में लोकतांत्रिक मूल्यों का ध्यान ना रखकर हमेशा चुनावी जीत को तरजीह दी है।

रामेश्वर मिश्रा

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जबरदस्त व्यूह रचना करके जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनावों में भाजपा को प्रचंड जीत दिलाकर उत्तर प्रदेश की सत्ता के सेमीफाइनल को भारी बहुमत से जीत कर अपने सभी विरोधियों को जबरदस्त झटका दिया और राज्य की आम जनता व राजनेताओं को भी स्पष्ट संदेश दे दिया है कि वह केवल संन्यासी या आम राजनेता नहीं हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश की राजनीति के चाणक्य और आम-जनमानस पर जबरदस्त पकड़ रखने वाले एक लोकप्रिय जननेता हैं।

चुनावी वर्ष में जिस तरह से उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर जीत के लिए सत्ता पक्ष भाजपा के साथ प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू कर रखी हैं, उसमें योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में अब भाजपा ने कहीं ना कहीं बढ़त बना ली है। जबकि राज्य के जमीनी हालातों पर नजर डाले तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों के लंबे समय से चल रहे आंदोलन व कोरोना की दूसरी जबरदस्त लहर के बाद उपजी जनता की नाराजगी, योगी लहर के चलते शांत होने के कगार पर है। राज्य में एक मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ की आम जन समुदाय के बीच लोकप्रियता आज भी बरकरार है। लोगों उन्हें मोदी व शाह के बाद हिन्दुत्व का सबसे बड़ा प्रतीक मानते हैं। वैसे भी देखा जाये तो भारत में प्रतीकों को मानने व उनके अनुसार चलने का चलन आदिकाल से रहा हैं, जिस पर योगी आदित्यनाथ एकदम खरे उतरते हैं। आज वे एक तरफ तो प्रदेश में हिन्दुत्व के सबसे बड़े ताकतवर प्रतीक बन कर'हिंदू हृदय सम्राट' वाली अपनी जबरदस्त छवि बनाकर बहुसंख्यक जनता के दिलोदिमाग पर छा गये हैं। वहीं प्रदेश में बहुत लंबे अरसे बाद वह एक ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं जिन पर व्यक्तिगत रूप से कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। लिहाजा, आज योगी आदित्यनाथ आम जनता के बीच एक बेहद ईमानदार सशक्त राजनेता के रूप में स्थापित हो चुकें हैं। आज वह राज्य की आम जनता के बीच में एक मठ के संन्यासी से राजनेता और अब बेहद लोकप्रिय जननेता के रूप में अपना स्थान बनाकर उनके दिलोदिमाग पर छा चुके हैं। देखा जाये तो उत्तर प्रदेश के आगामी चुनावी रण में जाने के लिए भाजपा के पास एक से एक दिग्गज चर्चित राजनेता मौजूद हैं। लेकिन, उनमें कोई भी ऐसा नेता नहीं है जो कि पूरे राज्य में आम जनता के बीच बेहद लोकप्रिय हो। आज के हालात में भाजपा के पास उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के विकल्प के तौर पर कोई राजनेता मौजूद नहीं है। भाजपा को राज्य में हर हाल में अपने स्टार प्रचारक मोदी, शाह व योगी के बलबूते ही चुनावी रण में जाना होगा। हिन्दुत्ववादी व ईमानदार छवि के चलते योगी आदित्यनाथ को अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बनाना होगा, तभी उसकी विजय पताका लहरायेंगी। वैसे भी राज्य में अभी तक तो योगी आदित्यनाथ के व्यक्तित्व को सत्ता पक्ष व विपक्ष के किसी भी नेता से कोई बड़ी चुनौती नहीं मिल पा रही है। राज्य में विपक्ष बिखरा हुआ है इसका उदाहरण जिला पंचायत के चुनावों में जनता ने देख लिया है, वैसे भी राज्य में विपक्षी दलों के पास अखिलेश यादव, मायावती व प्रियंका गांधी के अलावा कोई ऐसा लोकप्रिय चेहरा नहीं है जो क्षेत्रीय क्षत्रप हो या लोकप्रिय जननेता हो। लेकिन इन सभी की कार्यशैली व लक्ष्य केवल मुस्लिम वोटों को आकर्षित करने का रहता है। जिसकी वजह से अन्य मतदाता इन से दूर हो जाता है जिसकी वजह से राज्य में भाजपा को विशेष सकारात्मक ऊर्जा मिलती है और वह चुनावी लक्ष्य साधने में कामयाब हो जाती है। बहरहाल, यह तो आने वाला समय बतायेगा कि उत्तर प्रदेश की जनता वर्ष 2022 में किसके सिर पर सेहरा बांधती है। लेकिन, आज की परिस्थितियों में उत्तर प्रदेश में एक कुशल चुनावी रणनीतिकार के रूप में व लोकप्रिय जननेता के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की काट ढूंढना असंभव लग रहा है। फिलहाल, उत्तर प्रदेश में चुनावी वर्ष में योगी आदित्यनाथ चुनावी रणभूमि के एक अजेय योद्धा बने हुए हैं। जिनको मात देना विपक्षी दलों के लिए आसान नहीं लगता है। वैसे, चुनाव में शह और मात किसे मिलती है ये देखना दिलचस्प होगा।

चुनावी वर्ष में जिस तरह से उत्तर प्रदेश की 403 विधानसभा सीटों पर जीत के लिए सत्ता पक्ष भाजपा के साथ प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू कर रखी हैं, उसमें योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में अब भाजपा ने कहीं ना कहीं बढ़त बना ली है। जबकि राज्य के जमीनी हालातों पर नजर डाले तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसानों के लंबे समय से चल रहे आंदोलन व कोरोना की दूसरी जबरदस्त लहर के बाद उपजी जनता की नाराजगी, योगी लहर के चलते शांत होने के कगार पर है। राज्य में एक मुख्यमंत्री के रूप में योगी आदित्यनाथ की आम जन समुदाय के बीच लोकप्रियता आज भी बरकरार है। लोगों उन्हें मोदी व शाह के बाद हिन्दुत्व का सबसे बड़ा प्रतीक मानते हैं। वैसे भी देखा जाये तो भारत में प्रतीकों को मानने व उनके अनुसार चलने का चलन आदिकाल से रहा हैं, जिस पर योगी आदित्यनाथ एकदम खरे उतरते हैं। आज वे एक तरफ तो प्रदेश में हिन्दुत्व के सबसे बड़े ताकतवर प्रतीक बन कर'हिंदू हृदय सम्राट' वाली अपनी जबरदस्त छवि बनाकर बहुसंख्यक जनता के दिलोदिमाग पर छा गये हैं। वहीं प्रदेश में बहुत लंबे अरसे बाद वह एक ऐसे मुख्यमंत्री बने हैं जिन पर व्यक्तिगत रूप से कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा है। लिहाजा, आज योगी आदित्यनाथ आम जनता के बीच एक बेहद ईमानदार सशक्त राजनेता के रूप में स्थापित हो चुकें हैं। आज वह राज्य की आम जनता के बीच में एक मठ के संन्यासी से राजनेता और अब बेहद लोकप्रिय जननेता के रूप में अपना स्थान बनाकर उनके दिलोदिमाग पर छा चुके हैं।

‘बिहारी गुंडे’

वाले बयान पर

घिरीं टीएमसी सांसद

आरके सिंह

पश्चिम बंगाल से तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने आईटी कमिटी की बैठक में बिहारी गुंडे शब्द का प्रयोग किया, जिसके चलते सियासी हंगामा शुरू हो गया है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने इस बयान का विरोध करते हुए कहा कि टीएमसी सांसद का यह बयान न सिर्फ बिहारियों का अपमान है कि बल्कि पूरे हिंदी प्रदेश का अपमान करने वाला है। ऐसा बयान हिंदी भाषा भाषी राज्यों के लोगों के साथ नफरत फैलाने वाला है।इसके अलावा भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि टीएमसी को सभी हिंदी भाषी लोगों से एलर्जी है इसलिए उन्होंने मुझे ‘बिहारी गुंडा’ कहा। यह बिहार के स्वाभिमान पर हमला है। मैंने सभी तथ्य अध्यक्ष को सौंप दिए हैं। उन्हें माफी मांगनी चाहिए। वहीं टीएमसी सांसद के बयान पर बिहार भाजपा के विधायक हरि भूषण ठाकुर ने कहा कि ऐसी भाषा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। टीएमसी को शायद पता नहीं है कि एक बिहारी सौ पर भारी होता है। ऐसे सांसद पर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए वरना मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा।

वहीं जदयू ने टीएमसी सांसद के बिहारी गुंडे शब्द को भाषाई गुंडा बताया है। जदयू नेता नीरज कुमार ने कहा कि जिस भाषा का प्रयोग सांसद ने किया है वह भाषा ही गुंडई है। ऐसी भाषा के लम्पटीकरण पर कार्रवाई होनी चाहिए। बिहार चाणक्य और आर्यभट्ट की धरती रही है यहां ज्ञान की बात होती है ना कि गुंडई की। ऐसे बयानों के लिए सांसद को माफी मांगनी चाहिए और ऐसे बयान के खिलाफ उनपर कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए।

टीएमसी सांसद के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस एमएलसी प्रेमचंद्र मिश्रा ने इसे बिहार के साथ पूरे हिंदी भाषी प्रदेशों का अपमान बताया है। प्रेमचंद्र मिश्रा ने कहा कि ऐसे मामलों में किसी एक दल को नहीं बल्कि बिहार के सभी दलों को एक साथ मिलकर विरोध दर्ज कराना चहिये। वहीं राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि बिहार के बारे में ऐसी भाषा बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

हेमंत सरकार गिराने पर रार भाजपा-महागठबंधन में

तकरार

हेमंत सरकार गिराने के षड़यंत्र मामले में पुलिस गिरफ्तार आरोपियों के बयान की गंभीरता से जांच कर रही है। मामले को एक तरफ भाजपा नेता फेब्रिकेट बता रहे हैं तो वहीं महागठंबधन के नेता इसे सरकार गिराने की गहरी साजिश करार दे रहे हैं। उधर, गिरफ्तार तीन लोगों के पुलिस के सामने दिये बयान से चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पूरे मामले में सत्ता पक्ष के तीन विधायकों के नाम भी सामने आये हैं। आरोप की पुष्टि होने पर उक्त तीनों विधायकों से पूछताछ हो सकती है।

झारखंड की हेमंत सरकार गिराने के षड़यंत्र मामले में पुलिस गिरफ्तार आरोपियों के बयान की गंभीरता से जांच कर रही है। मामले को एक तरफ भाजपा नेता फेब्रिकेट बता रहे हैं तो वहीं महागठंबधन के नेता इसे सरकार गिराने की गहरी साजिश करार दे रहे हैं। उधर, गिरफ्तार तीन लोगों के पुलिस के सामने दिये बयान से चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पूरे मामले में सत्ता पक्ष के तीन विधायकों के नाम भी सामने आये हैं। आरोप की पुष्टि होने पर उक्त तीनों विधायकों से पूछताछ हो सकती है। जो हो, हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में तीन लोगों की गिरफ्तारी के बाद झारखंड की राजनीति गरम हो गयी है।

फिलहाल, हेमंत सोरेन सरकार को गिराने की साजिश को देखते हुए रांची पुलिस हरकत में है। जांच में आरोप की पुष्टि होने के बाद पुलिस तीनों विधायकों से पूछताछ कर सकती है। केस का आइओ सदर डीएसपी प्रभात रंजन बरबार को बनाया गया है तो एसआइटी में रांची की साइबर डीएसपी यशोधरा और खलारी डीएसपी अनिमेष नैथानी को भी शामिल किया गया है। गिरफ्तार बोकारो के अमित सिंह ने जेल भेजे जाने से पहले कोतवाली पुलिस को स्वीकारोक्ति बयान दिया है। कहा है कि 21 जुलाई को वह कार से भाई दीपू के साथ रांची आया था। रांची के मॉनसून रेस्टूरेंट में जय कुमार बेलखड़े ने फोन कर उसे बुलाया था। वहां पहुंचने पर अमित सिंह ने देखा कि जय कुमार के साथ अभिषेक दुबे और एक अन्य आदमी है। इन लोगों से मुलाकात के बाद वह एक विधायक से मिलने उसी दिन शाम सात बजे हजारीबाग सर्किट हाउस पहुंचा। वहां विधायक ने बातचीत के दौरान कहा कि हमारे सभी आठ विधायक तैयार हैं। आप लोग और चार विधायक की तालाश कर लिजीये। इसी दौरान उसे पता चला कि जय कुमार भी हजारीबाग सर्किट हाउस आनेवाला है। उसके आने से पहले वह वहां से निकल गया था।

हेमंत सरकार गिराने मामले में दो अलग-अलग टीम ने दिल्ली और मुंबई पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। यह टीम 15 जुलाई को दिल्ली एयरपोर्ट से आठ लोगों के निकलने की पड़ताल कर रही है। आठ लोगों में कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी, उमाशंकर अकेला व निर्दलीय विधायक अमित कुमार यादव, इनकी पत्नी सरिता देवी व उमाशंकर अकेला के पीएस हर्षवर्धन, कुमार गौरव के अलावा मामले में गिरफ्तार निवारण प्रसाद महतो, अमित सिंह व अभिषेक दुबे शामिल हैं।

अभिषेक ने बयान दिया था कि रांची एयरपोर्ट से इंडिगो के विमान से दिल्ली पहुंचने पर वहां के एयरपोर्ट पर महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री रहे चंद्रशेखर राव बावनकुले का भांजा जय कुमार बेलखड़े उन्हें रिसिव करने आया था। एयरपोर्ट पर पड़ताल के दौरान सीसीटीवी का साक्ष्य भी पुलिस जुटायेगी। बाद में वहां से टीम होटल विवांता भी जाएगी। वहां भी सभी की मौजूदगी की पड़ताल की जाएगी।

पूरे मामले में पुलिस यह भी देखेगी कि वहां पर भाजपा नेता चंद्रशेखर राव और चरण सिंह आये थे या नहीं। साथ ही विधायकों के 16 जुलाई के वापस लौटने की भी पड़ताल करेगी। दूसरी टीम मुंबई में भाजपा नेता चंद्रशेखर राव बावनकुले, चरण सिंह, जय कुमार बेलखड़े, मोहित भारतीय, अनिल कुमार, आशुतोष ठक्कर की गतिविधियों की भी पड़ताल करेगी। टीम मुंबई एयरपोर्ट से उक्त लोगों के रांची और दिल्ली दौरे के संबंध में जानकारी जुटायेगी। मामले में पुलिस की टीम होटल ली-लैक भी गयी। वहां पुलिस ने जय कुमार बेलखड़े, मोहित भारतीय, अनिल कुमार, अभिषेक दुबे और आशुतोष ठक्कर के साथ रेस्टूरेंट में खाना खाने का वीडियो फुटेज लिया है। इसमें महाराष्ट्र से आये लोग व अभिषेक दुबे के होटल ली-लैक में होने की पुष्टि हुई है। साथ ही होटल के रजिस्टर में भी महाराष्ट्र से आये चारों लोगों के नाम हैं। पुलिस ने चुटुपालू टोल प्लाजा से भी तीनों विधायकों की गाड़ियों की पड़ताल की है।

रिंकेश कुमार

देखा जा रहा है कि जिस समय सभी लोगों के दिल्ली जाने और आने की बात हो रही है, उस समय ये लोग टोल प्लाजा से गुजरे हैं या नहीं। साथ ही विधायकों और आरोपियों का मोबाइल लोकेशन भी पुलिस ले रही है, जिससे पता चलेगा कि कब-कब इन लोगों के बीच बात हुई और इनका लोकेशन क्या था।

अमित सिंह ने बयान में कहा है कि मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान उसकी मुलाकात एक सीआरपीएफ जवान से हुई थी। उसने जय कुमार से बात करायी। पांच जुलाई 2021 को जय कुमार ने उसको फोन कर कहा था कि तुम्हारे पास कुछ विधायक हैं? इस पर हमने कहा था कि हमारे एक करीबी निवारण महतो हैं, जिनके संपर्क में विधायक हैं। फिर निवारण ने गौरव कुमार उर्फ विनोद यादव से संपर्क किया। गौरव ने 14 जुलाई को हमें ओरमांझी बुलाया। उस दिन निवारण महतो के साथ मेरा भाई दीपू और मैं कार से ओरमांझी पहुंचे। वहां एक विधायक से मिले, लेकिन उनको पहचानते नहीं हैं। इसके बाद हजारीबाग गये। वहां गौरव कुमार उर्फ विनोद यादव और प्रवीण ने एक विधायक से मिलवाया। विधायक ने जय कुमार से फोन पर बात की। फिर दिल्ली जाने के लिए पांच आदमी का नाम दिया। जिसमें इंडिगो फ्लाइट में इनका टिकट बना। सभी 15 अप्रैल को रांची से दिल्ली गये।

आरोपियों के बयान के बाद कांग्रेस विधायकों के तार पूरे मामले से जुड़े हैं। कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी, उमाशंकर अकेला के दिल्ली दौरे को इससे जोड़कर देखा जा रहा है। कांग्रेस विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी ने भी बयान दिया है कि उनको बड़ा ऑफर मिला था। पूरे प्रकरण में कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम और प्रदेश अध्यक्ष डॉ रामेश्वर उरांव पूरी घटना की जानकारी ले रहे हैं। विधायकों से किसने, कब संपर्क किया, इसकी पूरी जानकारी जुटायी जा रही है। प्रदेश कांग्रेस विधायकों से बातचीत कर पूरी रिपोर्ट केंद्रीय नेतृत्व को दे सकता है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी आरपीएन सिंह ने कहा है कि विधायकों के नाम आये हैं, तो उसकी भी जांच हो रही है। पार्टी स्तर पर भी जानकारी जुटायी जा रही है। विधायकों ने हमेशा कहा है कि हम सभी इंटैक्ट हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने मामला भी दर्ज किया है। कई बातों का खुलासा हुआ है। अभी कई बातें सामने आनेवाली है। पहले पूरी तरह से मामले का खुलासा हो जाये, इसके बाद पार्टी स्तर पर भी देखा जाएगा।

सरकार गिराने मामले की सीबीआई जांच के लिए याचिका

हेमंत सोरेन सरकार गिराने के लिए विधायकों की खरीद-फरोख्त के मामले की सीबीआई जांच को लेकर झारखंड हाइकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गयी है। याचिका पंकज कुमार यादव की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने दायर की है। अदालत में दायर याचिका में पूरे प्रकरण की सीबीआई से जांच कराने की मांग की गयी है। इसके साथ ही मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय व आयकर विभाग से भी कराने का आग्रह किया गया है।

याचिकाकर्ता ने सीबीआई, आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय, बेरमो से कांग्रेस विधायक जयमंगल सिंह (अनूप सिंह), एसएसपी रांची आदि को प्रतिवादी बनाया है। प्रार्थी ने अधिकार का हवाला देते हुए याचिका में कहा है कि झारखंड के विधायक पद व पैसों के लिए अपना ईमान बेच देते हैं। यह वोटरों के संवैधानिक अधिकारों का हनन है। वर्ष 2005 से झारखंड में हॉर्स ट्रेडिंग की घटनाएं होती रही हैं। विधायक हमेशा सरकार बनाने में और राज्यसभा सदस्य चुनने में खुद को बेचते रहे हैं। इसलिए स्वयं को बेचनेवाले विधायकों और खरीदने वाली पार्टियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

याचिका में कहा गया है कि इस मामले में कई राज्यों के लोगों का नाम आ रहा है। इसलिए इसकी सीबीआई जांच जरूरी है। उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों विधायकों की खरीद फरोख्त कर हेमंत सरकार गिराने का आरोप लगाते हुए बेरमो से कांग्रेस विधायक जयमंगल सिंह ने रांची के कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी थी। इसी के आधार पर कोतवाली पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया था। फिलहाल, गिरफ्तार आरोपी न्यायिक हिरासत में बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार में बंद हैं।

सीसीटीवी से खुले राज दिखे 3 विधायक

रिंकेश कुमार

सरकार गिराने की साजिश और विधायकों की खरीद फरोख्त मामले की जांच के लिए दिल्ली गई टीम को सीसीटीवी फुटेज की जांच में कई सबूत हाथ लगे हैं। फुटेज की जांच में पुलिस ने पाया है कि 15 जुलाई की शाम होटल में झारखंड के कांग्रेसी विधायक इरफान अंसारी, उमाशंकर अकेला यादव और निर्दलीय विधायक अमित यादव की बैठक महाराष्ट्र के भाजपा नेता व पूर्व ऊर्जा मंत्री चंद्रशेखर राव बावनकुले और चरण सिंह के साथ हुई थी। सीसीटीवी में महाराष्ट्र से पूरे मामले की मध्यस्थता करने वाला पूर्व एनएसजी कमांडो व चंद्रशेखर राव बावनकुले का भगीना जयकुमार बलखेड़े भी है। रांची से तीनों विधायकों के साथ गए अभिषेक कुमार दुबे, अमित सिंह और निवारण कुमार महतो भी फुटेज में दिख रहे हैं।

रांची के खलारी डीएसपी अनिमेष नैथानी के नेतृत्व में दिल्ली गई जांच टीम ने होटल से 15, 16 व 17 जुलाई के फुटेज की मांग की थी। वहीं होटल हैरियर से भी 15 जुलाई का फुटेज मांगा गया था। 15 जुलाई की देर शाम होटल में एक साथ विधायक इरफान अंसारी, उमाशंकर अकेला, अमित यादव के अलावा महाराष्ट्र के चंद्रशेखर राव बावनकुले, चरण सिंह, जयकुमार बेलखेड़े व गिरफ्तार तीनों आरोपियों के बीच तकरीबन पंद्रह मिनट बैठक हुई थी। इसके बाद सभी लोग दो अलग-अलग एसयूवी से एक साथ निकलते भी फुटेज में दिख रहे हैं। मामले में गिरफ्तार अभिषेक कुमार दुबे ने स्वीकारोक्ति बयान मे खुलासा भी किया था कि होटल विवंता से निकलने के बाद महाराष्ट्र के भाजपा नेता तीनों विधायकों को पार्टी के बड़े नेताओं से मिलाने भी ले गए थे। लेकिन एक करोड़ की राशि एडवांस नहीं मिलने पर तीनों विधायक नाराज होकर लौट गए थे। हालांकि तीनों विधायक खरीद फरोख्त की बात का खंडन करते रहे हैं।

होटल के सीसीटीवी फुटेज जब्त होने के बाद अब रांची पुलिस इस मामले में तीनों विधायकों को नोटिस जारी करेगी। रांची पुलिस के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि भी की है कि दिल्ली से पुलिस टीम के लौटने के बाद विधायकों को नोटिस देकर पक्ष लिया जाएगा। वहीं इस मामले में महाराष्ट्र भाजपा के नेताओं के साथ होटल ली लैक से भागने वाले चार नेता व व्यवसायियों से भी पूछताछ की जाएगी। इसके लिए जल्द ही पुलिस टीम महाराष्ट्र जाएगी।

होटल के सीसीटीवी फुटेज जब्त होने के बाद अब रांची पुलिस इस मामले में तीनों विधायकों को नोटिस जारी करेगी। रांची पुलिस के अधिकारियों ने इस बात की पुष्टि भी की है कि दिल्ली से पुलिस टीम के लौटने के बाद विधायकों को नोटिस देकर पक्ष लिया जाएगा। वहीं इस मामले में महाराष्ट्र भाजपा के नेताओं के साथ होटल ली लैक से भागने वाले चार नेता व व्यवसायियों से भी पूछताछ की जाएगी। इसके लिए जल्द ही पुलिस टीम महाराष्ट्र जाएगी।

सिद्धू के बढ़े कद और अमरिंदर के लिए संकेत

नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष चुने जाने के साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के कद का क्या होगा? पर सवाल सियासी गलियारों में तैर रहे हैं। लेकिन यह देखना होगा कि अमरिंदर सिंह के लिए अब क्या संकेत है।

पंजाब प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू को चुने जाने के साथ ही राज्य के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के कद का क्या होगा? पर सवाल सियासी गलियारों में तैर रहे हैं। लेकिन यह देखना होगा कि अमरिंदर सिंह के लिए क्या संकेत है। कुछ महीने पहले तक कैप्टन अमरिंदर सिंह के समर्थकों को लग रहा था कि सबकुछ उन्हीं के मुताबिक हो रहा है। क्योंकि प्रमुख प्रतिद्वंद्वी शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) ने किसान कानूनों के मसले पर भाजपा से मतभेद के बाद राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) छोड़ दिया था। इस कानून के खिलाफ किसानों के किए जा रहे विरोध में आनंदित अमरिंदर सिंह ने कृषि कानूनों का एक वैकल्पिक स्वरूप पेश किया, जिसे विधानसभा में मजबूरन अकाली दल ने भी समर्थन दिया। ऐसे में पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह बहुत ही बेहतर स्थिति में नजर आ रहे थे। सबकुछ अपने मन माफिक देख वे आत्मविश्वास से इस कदर भरे हुए थे कि बीते साल नवंबर में उन्होंने सिद्धू को दोपहर के खाने पर बुलाया ताकि उनके साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा कर सकें। इससे पहले बीते साल जुलाई में नवजोत सिंह सिद्धू ने उस समय विरोध में इस्तीफा दे दिया था जब मुख्यमंत्री ने उन्हें स्थानीय निकाय विभाग के प्रभारी पद से हटा दिया था। तब अमरिंदर का कहना था कि सिद्धू का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं है। उन्होंने सिद्धू को बिजली विभाग देने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने इस उम्मीद में नया विभाग संभालने से इनकार कर दिया था कि नई दिल्ली (प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी) उनके साथ हुए अन्याय को समाप्त करेंगे। उसके बाद से लंबे समय तक सिद्धू और अमरिंदर सिंह के बीच बातचीत नहीं हुई। लेकिन, अगर दोपहर भोज दूरियां पाटने के लिए आयोजित था तो कहा जा सकता है कि बहुत देर हो चुकी थी। उस मुलाकात और उसके बाद की घटनाओं ने सिद्धू का रुख और अधिक कड़ा ही किया और वे इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाना चाहते थे। इसका नुकसान सुनील जाखड़ को उठाना पड़ा। उन्हें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से हटाकर सिद्धू को यह पद सौंप दिया गया।

सिद्धू ने अपनी नियुक्ति के फौरन बाद एक बैठक आयोजित की जहां 62 विधायक मौजूद थे। 117 सदस्यों वाली पंजाब विधानसभा में कांग्रेस को 77 सीट पर जीत मिली थी (बाद में उपचुनावों में यह तादाद बढ़कर 83 हो गई), यानी मुख्यमंत्री को न के बराबर समर्थन प्राप्त था। जाहिर है विधायकों को यह पता होता है कि उनके लिए कौन सा पक्ष बेहतर है। अगर वे सिद्धू के पक्ष में ज्यादा तादाद में नजर आए तो इसलिए क्योंकि उन्हें यह अहसास हो गया कि सिद्धू ही यह तय करेंगे कि वर्ष 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें दोबारा पार्टी का टिकट मिलेगा या नहीं। लेकिन, इसमें भी दो राय नहीं है कि अमरिंदर सिंह के पास अब कोई विकल्प नहीं है। उन पर उत्तराधिकार योजना थोप दी गई है। वह रूठ सकते हैं या लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन अब खेल का मैदान बराबरी का नहीं रह गया है। बहरहाल, अब अमरिंदर सिंह की ताकत और उपलब्धियों पर नजर डालने की जरूरत है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 13 में से नौ लोकसभा सीट पर जीत मिली थी। टिकट वितरण में अगर थोड़ी समझदारी बरती जाती तो पार्टी आसानी से 10 सीट जीत सकती थी। पार्टी को हर उपचुनाव में जीत मिली और उसने स्थानीय निकाय का भी हर चुनाव जीता। अमरिंदर के समर्थक कहते हैं कि अमरिंदर सिंह भी कोई नैतिकता की प्रतिमूर्ति नहीं हैं। उनका काम करने का अपना तरीका है और वे ऐसे ही हैं। लेकिन, वे यह भी मानते हैं कि दिल्ली में जो भी कवायद हुई वह इस तरह तैयार की गई थी कि उन्हें सिद्धू का आधिपत्य स्वीकार करना पड़े। उल्लेखनीय है कि पंजाब में 38 फीसदी हिंदू हैं। आतंकवाद की शुरूआत के पहले प्रदेश में हिंदुओं की तादाद 48 फीसदी थी। लेकिन, पिछले दो दशक में यह तादाद कम हुई है। करीब 31 फीसदी दलित हैं जो हिंदुओं और सिखों में बंटे हुए हैं लेकिन सिख दलित अधिक हैं। 78 फीसदी दलित आबादी पंजाब के ग्रामीण इलाकों में रहती है। पारंपरिक तौर पर देखें तो कांग्रेस को पंजाब में हिंदुओं और दलितों की बदौलत जीत मिली। यह भी सही है कि उनमें पंथ के आधार पर बंटवारा है-रामदासिया, रविदासिया, वाल्मीकि आदि। हिंदुओं में भी विभाजन है। जाट सिखों की तादाद 18 से 22 फीसदी है और सन 1977 से ही पंजाब की राजनीति पर कांग्रेस का दबदबा है।

पंजाब का हर मुख्यमंत्री कोई न कोई जाट सिख ही रहा है। अब तो मुख्यमंत्री और पंजाब कांग्रेस कमेटी के प्रमुख दोनों ही जाट सिख हैं। ऐसे में सवाल ये है कि सिद्धू पार्टी और कार्यकताओं को कितनी अच्छी तरह जानते हैं। क्योंकि, वे भाजपा से कांग्रेस में आए हैं और आज भी उनका दावा है कि राजनीति में अरुण जेटली उनके गुरु हैं? सिद्धू महत्त्वाकांक्षी और जल्दबाजी में नजर आते हैं और इसके लिए उन्हें दोष भी नहीं दिया जा सकता। मगर, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की उग्रता का सामना करने की वजह से वे एक ऐसी पार्टी को लेकर चुनावी तैयारी में लग जाएंगे जो उनके प्रति वफादार रही है। लेकिन, ऐसी पार्टी चुनाव जीत सकती है या नहीं यह एकदम अलग मसला है। आने वाले समय में जो चुनाव होने वाले हैं उनमें उत्तर प्रदेश के चुनाव सबसे अहम होंगे। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण चुनाव कर्नाटक और पंजाब का चुनाव होगा।

विकास शर्मा

पुरानी डील पर माने नीतीश

मोदी ने नहीं बढ़ने दिया भाव

मोदी कैबिनेट में एक मात्र मंत्री पद के साथ जदयू का शामिल होना चौंकाने वाली बात है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साल 2019 में पीएम मोदी की ओर से केंद्रीय कैबिनेट में एक मंत्री पद के ऑफर को ठुकरा दिया था। उस समय कहा गया था कि जदयू मजबूती के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होगी, लेकिन दो साल बाद भी ऐसा नहीं हो पाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जदयू के एक मात्र नेता के शामिल होते ही साफ हो चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र की राजनीति में नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जदयू को ज्यादा तवज्जो देने के मूड में नहीं हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मौजूदा सरकार के करीब दो साल पूरे होने पर मंत्रिमंडल विस्तार किया है। कुल 43 मंत्रियों को शपथ दिलाई गयी है। मंत्रिमंडल विस्तार में एनडीए के घटक दल जनता दल युनाइटेड (जदयू) के एक मात्र नेता रामचंद्र प्रसाद सिंह को जगह मिली है। मोदी कैबिनेट में एक मात्र मंत्री पद के साथ जदयू का शामिल होना चौंकाने वाली बात है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साल 2019 में पीएम मोदी की ओर से केंद्रीय कैबिनेट में एक मंत्री पद के ऑफर को ठुकरा दिया था। उस समय कहा गया था कि जदयू मजबूती के साथ केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल होगी, लेकिन दो साल बाद भी ऐसा नहीं हो पाया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में जदयू के एक मात्र नेता के शामिल होते ही साफ हो चुका है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र की राजनीति में नीतीश कुमार और उनकी पार्टी जदयू को ज्यादा तवज्जो देने के मूड में नहीं हैं।

क्या था नीतीश का फॉम्यूर्ला

वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में जदयू को एक केंद्रीय मंत्री का पद ऑफर किया गया था। इसके बाद तत्कालीन जदयू अध्यक्ष और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा था कि लोकसभा चुनाव में भाजपा और जदयू बिहार की 40 में से 17-17 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे, जिसमें से नीतीश की पार्टी को 16 और पीएम मोदी के दल को 17 सीटें आई थीं। एनडीए की अन्य घटक दल एलजेपी सभी 6 सीटें जीती थी। नीतीश कुमार का कहना था कि चुनाव में सीट बंटवारे की तरह केंद्रीय मंत्रिमंडल में भी दोनों दलों की सहभागिता 50-50 फॉम्यूर्ले पर होगी। 2019 में सरकार गठन के दौरान पीएम मोदी ने कैबिनेट गठन के दौरान नीतीश कुमार की यह शर्त मानने से इनकार कर दिया था। इसके बाद नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि जदयू सरकार में शामिल नहीं होगी। इसके दो साल बाद मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ है। माना जा रहा था कि इस बार जदयू अपने तीन या इससे ज्यादा नेताओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करा लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया है।

एक पर क्यों माने सुशासन बाबू

नीतीश कुमार के राजनीतिक फैसलों पर नजर डालें तो यह बात स्पष्ट है कि वह जब भी किसी के साथ गठबंधन करते हैं तो हमेशा बराबरी की हिस्सेदारी चाहते हैं। अपने राजनीतिक कॅरियर में शायद ही कोई मौका हो जब नीतीश कुमार ने किसी दल के साथ कोई डील की हो और वह उसमें छोटे भाई की भूमिका में दिखे हों। यह पहला मौका है जब नीतीश कुमार डील में झुके हुए दिख रहे हैं।

नीतीश कुमार से जब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधे-सीधे कन्नी काट ली। उन्होंने साफ तौर से कहा कि 2019 में वह जेडीयू अध्यक्ष थे इसलिए वह फैसला ले रहे थे कि पार्टी केंद्र सरकार में शामिल होगी या नहीं। इस वक्त आरसीपी सिंह जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं इसलिए इस तरह के फैसले लेने के लिए वही अधिकृत हैं।

वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव में भले ही भाजपा से जदयू केवल एक सीट पीछे रही थी, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में परिणाम बिल्कुल ही उलट गये थे। एनडीए गठबंधन में भाजपा 74 सीटों के साथ नंबर वन पार्टी बनी जबकि जेडीयू को 43 सीटों से संतोष करना पड़ा था। चुनाव परिणाम में जदयू के तीसरे नंबर की पार्टी होने के बाद भी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठाया गया है। माना जाता है कि भाजपा का बिहार नेतृत्व कतई नहीं चाहता था कि मुख्यमंत्री का पद जदयू के पास जाए। भाजपा की केंद्रीय नेतृत्व की दखल के चलते नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी पर बैठाया गया। यह बात खुद नीतीश कुमार भी पत्रकारों के सामने कबूल कर चुके हैं।

ऐसे में सवाल उठना लाजिमी है कि क्या नीतीश कुमार बिहार में अपनी सीएम की कुर्सी बचाने के लिए केंद्र में एक मात्र मंत्री पद से संतुष्ट हो गए हैं। पिछले कुछ दिनों से बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल कई मौकों पर सीएम नीतीश के मनमाने रवैये पर सवाल उठा चुके हैं। इसके अलावा डिप्टी सीएम और बिहार भाजपा के वरिष्ठ नेता तारकिशोर प्रसाद सिंह भी पार्टी कार्यकताओं के सामने कबूल कर चुके हैं कि बिहार की मौजूद सरकार में भाजपा की छाप नहीं दिख रही है। वर्ष 2019 में जब मोदी कैबिनेट का गठन हुआ था तब बिहार से रविशंकर प्रसाद, गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, अश्विनी चौबे, आरके सिंह और रामविलास पासवान को मंत्री बनाया गया था। रामविलास पासवान का निधन हो चुका है। वहीं रविशंकर प्रसाद से इस्तीफा ले लिया गया है। यानी अब मोदी मंत्रिमंडल में बिहार से केवल गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, आरके सिंह और अश्विनी चौबे बचे हैं। वहीं इस लिस्ट में दो नये चेहरे पशुपति कुमार पारस और आरसीपी सिंह का नाम जुट गया है। मंत्रिमंडल विस्तार में आरके सिंह के कद में वृद्धि की गई है।

मोहित कुमार

मंत्रिमंडल विस्तार

एक पर भी खुश नीतीश !

> मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद कहते हैं कि जब वो पुड़िया बांधकर फेंकते हैं तो वो खुलती नहीं। तो फिर जिस एक मंत्रिपद को 2019 में नीतीश ने सांकेतिक बताकर मोदी सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया था, वही सांकेतिक पद दो साल बाद उन्हें क्यों कबूल हो गया? इसकी वजह भी बड़ी है। केंद्र की मोदी सरकार के कैबिनेट विस्तार के बाद चर्चा इसी बात की है कि चिराग को दूसरा झटका देने के लिए नीतीश ने अपनी मांगों की कुबार्नी दे दी। दरअसल जैसे ही पशुपति पारस को केंद्र सरकार में शामिल करने का फैसला लिया गया उसी वक्त नीतीश ने चिराग को दूसरा झटका दे दिया। छखढ सांसद होने के नाते पशुपति पारस को केंद्र सरकार में बतौर खाद्य प्रसंस्करण मंत्री शामिल कर लिया गया।

> चर्चाएं थीं कि जदयू को केंद्रीय कैबिनेट में ज्यादा नुमाइंदगी मिल सकती है, लेकिन फाइनल लिस्ट आने पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद सिंह को ही कैबिनेट मंत्री के तौर पर मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। उन्हें मोदी सरकार में इस्पात मंत्री बनाया गया है। आरसीपी सिंह के मंत्री बनने पर उन्हें लगातार बधाई संदेश मिल रहे हैं। लेकिन, बिहार के सीएम नीतीश कुमार की चुप्पी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। हर कोई यही जानना चाह रहा है कि आखिर उन्होंने आरसीपी सिंह को बधाई वाला ट्वीट क्यों नहीं किया? क्या नीतीश किसी वजह से नाराज हैं?

जदयू के सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार ने केंद्र में 3 मंत्रिपद मांगे, लेकिन एक ही मिला। बावजूद इसके वो खुश तो बहुत होंगे! ये चर्चा यूं ही नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद कहते हैं कि जब वो पुड़िया बांधकर फेंकते हैं तो वो खुलती नहीं। तो फिर जिस एक मंत्रिपद को 2019 में नीतीश ने सांकेतिक बताकर मोदी सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया था, वही सांकेतिक पद दो साल बाद उन्हें क्यों कबूल हो गया? इसकी वजह भी बड़ी है। केंद्र की मोदी सरकार के कैबिनेट विस्तार के बाद चर्चा इसी बात की है कि चिराग को दूसरा झटका देने के लिए नीतीश ने अपनी मांगों की कुबार्नी दे दी। दरअसल, जैसे ही पशुपति पारस को केंद्र सरकार में शामिल करने का फैसला लिया गया उसी वक्त नीतीश ने चिराग को दूसरा झटका दे दिया। लोजपा सांसद होने के नाते पशुपति पारस को केंद्र सरकार में बतौर खाद्य प्रसंस्करण मंत्री शामिल कर लिया गया है। पारस को केंद्र सरकार में शामिल करने का सीधा मतलब था कि भाजपा उनकी अगुवाई वाली लोजपा को कबूल कर चुकी है। नीतीश भी तो यही चाहते थे। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में चिराग के हाथों 20 से ज्यादा सीटों पर चोट खा चुके नीतीश कुमार बदला चाहते थे। लेकिन, चिराग खुद को पीएम मोदी का हनुमान बताकर उनके सामने एक ढाल खड़ी कर देते थे।एक तरह से एलजेपी सांसद पशुपति कुमार पारस को कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल करने और उन्हें खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का प्रभार देने का पीएम नरेंद्र मोदी का फैसला चिराग पासवान के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ। वो भी तब जब चिराग ये कहते आ रहे थे कि वो पीएम मोदी के हनुमान हैं। पारस के मोदी सरकार में शामिल होने को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक और जीत के रूप में ही देखा जा रहा है। एक फिल्मी डॉयलॉग है कि'हार कर जीतने वाले को ही बाजीगर कहते हैं'। चिराग पासवान के मामले में अगर नीतीश को भी बिहार की सियासत का बाजीगर कहा जाए तो गलत न होगा। भले ही उनकी तीन मंत्रियों वाली मांग भाजपा ने नहीं मानी लेकिन नीतीश पारस के मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद चिराग को दूसरा झटका तो दे ही चुके हैं।

मोहित कुमार

अपने मंत्री को नीतीश ने नहीं दी बधाई

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए-2 सरकार में जदयू भी शामिल हो गई है। हालांकि, ऐसी चर्चाएं थीं कि जदयू को केंद्रीय कैबिनेट में ज्यादा नुमाइंदगी मिल सकती है, लेकिन फाइनल लिस्ट आने पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद सिंह को ही कैबिनेट मंत्री के तौर पर मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। उन्हें मोदी सरकार में इस्पात मंत्री बनाया गया है। आरसीपी सिंह के मंत्री बनने पर उन्हें लगातार बधाई संदेश मिल रहे हैं। लेकिन, बिहार के सीएम नीतीश कुमार की चुप्पी को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। हर कोई यही जानना चाह रहा है कि आखिर उन्होंने आरसीपी सिंह को बधाई वाला ट्वीट क्यों नहीं किया? क्या नीतीश किसी वजह से नाराज हैं?

क्या आरसीपी के मंत्री बनने से खुश नहीं है नीतीश? ये सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि आरसीपी सिंह को नीतीश कुमार का बेहद करीबी माना जाता है। इतनी अहम जिम्मेदारी पर उनके ट्वीट का इंतजार तो सभी को रहता है। वैसे भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर बेहद एक्टिव रहते हैं। लेकिन इस बार उनकी चुप्पी सियासी गलियारे में हलचल पैदा कर रही है। वहीं सियासी जानकारों के मुताबिक, नीतीश की इस चुप्पी के पीछे की वजह बेहद खास है। दरअसल, बिहार के मुख्यमंत्री ये नहीं जताना चाहते हैं कि आरसीपी सिंह को मिली जिम्मेदारी से वो ज्यादा खुश हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो पार्टी में नाराजगी और बढ़ सकती है।

कैबिनेट विस्तार पर चर्चा के दौरान पार्टी के कद्दावर नेता राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल करने की अटकलें थीं। हालांकि, ऐसा नहीं हुआ। कहा ये भी जा रहा कि जदयू नेतृत्व की ओर से केंद्र में 3 मंत्री पद की डिमांड थी लेकिन मिला एक। इससे पहले 2019 में नीतीश ने केंद्रीय कैबिनेट में सांकेतिक भागीदारी बताकर मोदी सरकार में शामिल होने से इनकार कर दिया था, लेकिन अब सांकेतिक पद दो साल बाद उन्हें क्यों कबूल हो गया? ये सब कई सवाल हैं जिन पर पार्टी में चर्चा का दौर शुरू हो सकता है। सियासी जानकारों के मुताबिक, ऐसी किसी भी स्थिति को टालने के लिए ही नीतीश ने कैबिनेट विस्तार को लेकर चुप्पी साधने का फैसला लिया। दूसरी ओर रामचंद्र प्रसाद सिंह ने देश के नए इस्पात मंत्री का पदभार संभाल लिया। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान की जगह ली, जिन्हें मोदी सरकार के नए कैबिनेट फेरबदल में शिक्षा मंत्रालय के साथ कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आरसीपी सिंह जदयू की ओर से राज्यसभा में बिहार का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह 1984 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं और उन्होंने विभिन्न पदों पर रहकर 25 वर्षों से अधिक समय तक सेवा की है।

केंद्रीय मंत्रिमंडल में हिस्सेदार

पहली बार कोडरमा

रिंकेश कुमार

आजादी के बाद और 1977 में कोडरमा संसदीय क्षेत्र के गठन के बाद अबतक एकबार भी इस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्रिमंडल में नहीं होने के कारण विकास की कोई बड़ी इबारत नहीं लिखी जा सकी है। ऐसे में स्वाभाविक है कि लोगों को सांसद और अब केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी से काफी उम्मीदें हैं। इससे पहले स्व. रीतलाल प्रसाद वर्मा और तिलकधारी प्रसाद सिंह जैसे नेता ने भी कोडरमा संसदीय क्षेत्र से प्रतिनिधित्व किया। लेकिन, पहली बार कोडरमा के सांसद को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकी है।

झारखंड के कोडरमा लोकसभा क्षेत्र की सांसद सह भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अन्नपूर्णा देवी को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने के बाद राज्य के लोगों की अपेक्षा बढ़ गयी है। केंद्रीय मंत्रीमंडल में पहली बार कोडरमा संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व हुआ है। इससे पहले स्व. रीतलाल प्रसाद वर्मा और तिलकधारी प्रसाद सिंह जैसे नेता ने भी कोडरमा संसदीय क्षेत्र से प्रतिनिधित्व किया। लेकिन, पहली बार कोडरमा के सांसद को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिल सकी है। माना जा रहा है अन्नपूर्णा देवी के केंद्रीय मंत्री बनने से झारखंड के विकास में तेजी आएगी और वर्षों से लंबित कई योजनाओं का तेजी से क्रियान्वयन हो सकेगा। अन्नपूर्णा देवी का संबंध संथाल परगना प्रमंडल से जुड़ा हुआ है और वह इस क्षेत्र की बेटी हैं ।

वर्ष 1993 में अन्नपूर्णा देवी की शादी जनता दल से कोडरमा विधायक रमेश यादव से हुई। पति राजनीति में थे, लेकिन अन्नपूर्णा देवी उनके रहते सार्वजनिक जीवन में नहीं रहीं। शादी के पांच साल हुए ही थे कि पति का आकस्मिक निधन हो गया। उनके समक्ष चुनौती घर-परिवार के साथ-साथ परिवार के राजनीतिक विरासत को संभालने की थी। वर्ष 1998 में जब उन्होंने घर की दहलीज से बाहर निकलकर राजनीति में कदम रखा। रमेश यादव के निधन के चलते 1998 में कोडरमा सीट पर हुए विधानसभा उपचुनाव में राजद ने उन्हें उम्मीदवार बनाया और उन्होंने जीत हासिल की।

अन्नपूर्णा देवी ने राजनीतिक विरासत को बखूबी संभाला और वर्ष 1998 से 2014 तक लगातार कोडरमा विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करती रहीं। वर्ष 2000 में वह एकीकृत बिहार के राबड़ी देवी सरकार में खान एवं भूतत्व राज्यमंत्री रह चुकी हैं। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद राज्य बंटा और इनका मंत्री पद चला गया। जुलाई 2013 में हेमंत सोरेन की सरकार में अन्नपूर्णा देवी प्रदेश की जल संसाधन, महिला एवं बाल विकास मंत्री बनी। हांलाकि 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में वह चुनाव हार गयीं। वर्ष 2019 में राजद की प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उन्होंने अप्रत्याशित निर्णय लेते हुए भाजपा का दामन थाम लिया। भाजपा ने इन्हें प्रत्याशी बनाया और तब इन्होंने दिग्गज नेता बाबूलाल मरांडी को बडे. अंतर से हराया। इसके बाद उन्हें भाजपा का प्रदेश उपाध्यक्ष और फिर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। आजादी के बाद और 1977 में कोडरमा संसदीय क्षेत्र के गठन के बाद अबतक एकबार भी इस संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्रिमंडल में नहीं होने के कारण विकास की कोई बड़ी इबारत नहीं लिखी जा सकी है। ऐसे में स्वाभाविक है कि लोगों को सांसद और अब केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी से काफी उम्मीदें हैं। लगातार 23 वर्षों से इलाके का प्रतिनिधित्व कर रहीं अन्नपूर्णा देवी की गिनती राज्य के वरीय नेताओं में होती हैं। अन्नपूर्णा देवी जन्म स्थान दुमका जिले के मसलिया प्रखंड के अजमेरी गांव में हुआ था। पिता ताराप्रसन्न महतो, माता रेवती देवी की पुत्री अन्नपूर्णा देवी दो भाई और सात बहनों में सबसे छोटी हैं।

बंगाल से बनाये 4 नये मंत्री

मंत्रिपरिषद में शामिल हुए पश्चिम बंगाल के चार नए चेहरों से संदेश साफ है कि पार्टी ने उन इलाकों को पुरस्कार दिया है, जहां पर 2021 के विधानसभा चुनाव में उसकी जमीन मजबूत हुई है। पीएम मोदी ने भले ही पर्यावरण राज्यमंत्री बाबुल सुप्रियो और महिला और बाल विकास राज्यमंत्री देबाश्री चौधरी से इस्तीफा लिया है, लेकिन शांतनु ठाकुर, जॉन बारला, डॉ सुभाष सरकार और सबसे युवा चेहरे निसिथ प्रमाणिक की मंत्रिपरिषद में एंट्री इस बात का प्रमाण है कि भाजपा ने बंगाल में खास वोट बैंक को सम्मानित करके मिशन 2024 का बिगुल अभी से फूंक दिया है।

विश्वजीत घोष

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्रिपरिषद में शामिल हुए पश्चिम बंगाल के चार नए चेहरों से संदेश साफ है कि पार्टी ने उन इलाकों को पुरस्कार दिया है, जहां पर 2021 के विधानसभा चुनाव में उसकी जमीन मजबूत हुई है। पीएम मोदी ने भले ही पर्यावरण राज्यमंत्री बाबुल सुप्रियो और महिला और बाल विकास राज्यमंत्री देबाश्री चौधरी से इस्तीफा लिया है, लेकिन शांतनु ठाकुर, जॉन बारला, डॉ सुभाष सरकार और सबसे युवा चेहरे निसिथ प्रमाणिक की मंत्रिपरिषद में एंट्री इस बात का प्रमाण है कि भाजपा ने बंगाल में खास वोट बैंक को सम्मानित करके मिशन 2024 का बिगुल अभी से फूंक दिया है।

पश्चिम बंगाल के कूचबिहार इलाके से आने वाले 35 साल के निशिथ प्रमाणिक पीएम मोदी की टीम के सबसे नौजवान मंत्री हैं। मोदी की युवा टीम में प्रमाणिक की एंट्री कितनी महत्वपूर्ण है, यह इसी से पता चलता है कि उन्हें गृह राज्यमंत्री जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गयी है। बंगाल से आने वाले जूनियर गृह राज्य मंत्री के मंत्रालय का संबंध अमित शाह के मंत्रालय से होना ही बंगाल की राजनीति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। वह राजबंशी समाज के भी नेता हैं। प्रमाणिक उत्तर बंगाल से आते हैं, जहां पर राजबंशी वोट बैंक की बदौलत भाजपा ने विधानसभा चुनावों में बेहतर प्रदर्शन किया है।

दरअसल, उत्तर बंगाल में तीन मुख्य मुद्दे हैं- आदिवासी वोट, चाय बागान का मुद्दा और राजवंशी वोट बैंक। विधानसभा चुनाव में भाजपा इन सभी को साधने में सफलता पाई है और अब उसकी नजर इनके जरिए 2024 के चुनाव पर है। उत्तर बंगाल से एक और भाजपा सांसद को राज्यमंत्री बनाया गया है। आदिवासी समाज से आने वाले जॉन बारला हाल ही में पिछड़ेपन के चलते उत्तर बंगाल को केंद्र शासित प्रदेश बनाने की मांग करके सुर्खियों में आ चुके हैं। 2021 के विधानसभा चुनावों में अलीपुरद्वार से भाजपा सारी सीटें जीत गई, जिसमें बारला की भूमिका अहम मानी जा रही है। इसलिए उन्हें मुख्तार अब्बास नकवी के जूनियर मंत्री के रूप में अल्पसंख्यक मामलों का राज्यमंत्री बनाये जाने की वजह समझी जा सकती है। उनके जरिए भाजपा की नजर उस आदिवासी वोट बैंक पर है, जो 2024 में उसके लिए बहुत काम आ सकता है।

इसी तरह से दक्षिण बंगाल में भाजपा का गणित मतुआ समुदाय और जंगल महल इलाके में फिट बैठा है। 38 साल के शांतनु ठाकुर को जहाजरानी मंत्रालय में राज्यमंत्री बनाना उसी की ओर इशारा है कि बंगाल में आगे भी मतुआ समुदाय बीजेपी के लिए मायने रखने जा रहा है। मतुआ बहुल इलाके में भाजपा ने अपना मजबूत जनाधार तैयार किया है, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान (बांग्लादेश) से आए मतुआ समाज के लोगों के लिए भारतीय नागरिकता का मुद्दा भाजपा के लिए हमेशा से अहम रहा है।

दूसरी ओर डॉ सुभाष सरकार संघ के बैकग्राउंड से हैं और पेशे से भी डॉक्टर हैं। वह जंगल महल इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं। उन्हें नये कैबिनेट विस्तार के बाद शिक्षा राज्यमंत्री बनाया गया है। जाहिर है कि जंगल महल वो इलाका है, जिससे अभी भी भाजपा को काफी उम्मीदें हैं। हालांकि, तृणमूल प्रवक्ता कुणाल घोष नहीं मानते कि कैबिनेट विस्तार के जरिए भाजपा का कोई गणित बंगाल में चलने वाला है। जो भी हो यह दिलचस्प है कि बंगाल हारने के बाद भी भाजपा का वहां पर हौसला नहीं टूटा है और अभी से अगले चुनाव के लिए गोटी सेट करने में जुट चुकी है।

अंडर वर्ल्ड क्वीन जेनाबाई इशारों पर नाचते थे दाऊद

एक दौर था जब इलाके में कोई जेनाबाई से ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकता था। यह वो दौर था जब अंडरवर्ल्ड डॉन बनने वाला दाऊद उसकी जी हुजूरी करता था। दाऊद के गॉडफादर हाजी मस्तान के लिए जेनाबाई तो अपनी बहन जैसी थी। बंबई का दिग्गज करीम लाला उसकी चौखट पर दस्तक देता था। तमिल डॉन वर्दराजन मुनिस्वामी मुदलियार का धंधा जेनाबाई की रहम पर चलता था। उस दौर में यह पूरा गैंग लोगों की किस्मत के फैसले करता था।

रंजीत कुमार
मुख्य संपादक और सीईओ
(जेट न्यूज व 24 जेट न्यूज डॉट कॉम)

वह औरत थी, मगर तूफान से कम नहीं। नाम था जेनाबाई। वह अंडर वर्लड क्वीन थी और दबंगों की दबंग भी। उसे पुलिस की वॉर्निंग भी घर में कैद नहीं रख पाई। उस वक्त वह लोगों के बीच शांति का पैगाम लेकर पहुंची, जब बाबरी विध्वंस के बाद दंगे भड़के थे। ये 1993 की जेनाबाई थी। मगर एक दौर था, जब इलाके में कोई उससे ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकता था। जब अंडरवर्ल्ड डॉन बनने वाला दाऊद उसकी जी हुजूरी करता था और दाऊद का गॉडफादर हाजी मस्तान उसको अपनी बहन कहता था। करीम लाला जब उसकी चौखट पर दस्तक देता था। और, तमिल डॉन वर्दराजन मुनिस्वामी मुदलियार का धंधा उससे ही चलता था।

एक समय आया जब जेनाबाई की ताकत दिखी थी। बाबरी विध्वंस की खबर फैलने के बाद घनघोर दंगे हुए, जिसकी आंच बंबई तक पहुंची थी। डोंगरी का इलाका भी दंगों में झुलस रहा था। दंगों की यह आग उस वक्त ज्यादा फैल गई, जब 9 जनवरी 1993 को सुलेमान उस्मान बेकरी में स्पेशल फोर्स ने गोली चलाई, क्योंकि इस बेकरी के ऊपर मदरसा था। दावा था यहां आतंकी हैं, जो धमाकों की साजिश रच रहे हैं। 9 मुसलमान मारे गए। जब लाशें बाहर लाई गईं तो उनमें पांच तो बेकरी मालिक अब्दुल सत्तार के कर्मचारी थे। चीख पुकार और गोलियों की गूंज के बीच जहनी सन्नाटों में रोते बिलखते लोग थे। यह मंजर एक बूढ़ी औरत अपने घर की खिड़की से देख रही थी। उसने चादर उठाकर अपने ऊपर लपेटी। रंग चिट्टा, जेवरात से लदी हुई। एक हाथ में तस्बीह (माला) तो दूसरे में सफेद झंडा। ऐलानिया सख्ती में उसने कहा-''ऐ मेरे लोगों। प्यारे लोगों... क्या हो गया है तुम्हें। आओ हम मिलकर चलें। लगाओ नारा- हम एक हैं। ये हिंदुस्तान अपना है। यह इलाका अपना है। फिर, क्यों आग लगाते हो इस चमन को। सुन लो मेरी बात गौर से। अब तुम्हें अगर इस शहर को जलाना है तो मेरी लाश से गुजरना होगा।''

जेनाबाई डोंगरी की जली हुई गलियों से होकर पुलिस स्टेशन की तरफ चल पड़ी। पीछे पीछे नौजवानों की तादाद पहले एक, फिर दो और इस तरह हुजूम बढ़ता गया। अब नारों की आवाज बर्बाद हो चुकी गलियों में गूंजने लगी। लोगों के नारे-'जेनाबाई जिंदाबाद, जेनाबाई जिंदाबाद, जेनाबाई जिंदाबाद' जमीन से फलक तक जाने लगे। जेनाबाई को पुलिस की वॉर्निंग भी घर में कैद नहीं रख पाई। वह लोगों के बीच शांति का पैगाम लेकर पहुंची। और, दंगाइयों के सामने बेखौफ होकर खड़ी हो गई। जेनाबाई की यह ताकत वर्ष 1993 की थी। मगर, एक दौर था जब इलाके में कोई उससे ऊंची आवाज में बात भी नहीं कर सकता था। यह वो दौर था जब अंडरवर्ल्ड डॉन बनने वाला दाऊद उसकी जी हुजूरी करता था।

दाऊद के गॉडफादर हाजी मस्तान के लिए जेनाबाई तो अपनी बहन जैसी थी। बंबई का दिग्गज करीम लाला उसकी चौखट पर दस्तक देता था। तमिल डॉन वर्दराजन मुनिस्वामी मुदलियार का धंधा जेनाबाई की रहम पर चलता था। उस दौर में यह पूरा गैंग लोगों की किस्मत के फैसले करता था।

एक बार दाउद के गॉड फादर हाजी मस्तान ने जेनाबाई को खाने पर बुलाया था। पूरे इंतजामात थे। हाजी मस्तान ने ड्राइवर से कहा था कि''डोंगरी गाड़ी ले जाओ। आपा जेनाबाई को मैंने आज शाम के खाने पर बुलाया है। ठीक से लेकर आना रास्ते में तकलीफ ना हो कोई।'' यह वर्ष 1980 की बात है। जिसका जिक्र लेखक एस हुसैन जैदी ने अपनी किताब में भी किया है। एक लंबी सी कार डोंगरी में चूनावाला बिल्डिंग के पास आकर रुकी। 14 साल की थीं जेनाबाई, जब इस बिल्डिंग के पहले फ्लोर पर ब्याहकर आई थीं। उनकी शादी लकड़ी का छोटा सा कारोबार करने वाले मोहम्मद शाह दरवेश से हुई थी। उस वक़्त जेनाबाई की पहचान जैनब दरवेश के नाम से थी। जो बाद में गुजराती व्यापारियों के संपर्क में आने के बाद जेनाबाई हो गई। कानों में सोने के झुमके। चिकन का सफेद कुर्ता पहनें। ऊपर से शॉल डाले हुए। बड़े एटिट्यूड के साथ जेनाबाई बाहर आईं। ड्राइवर ने गाड़ी का गेट खोला। जेनाबाई के बैठते ही गाड़ी चल पड़ी। चॉल वाले इलाके में इस तरह गाड़ी आना और जेनाबाई का जाना, सबको खबर थी कि जेनाबाई कहां जाती हैं। और, उनके ताल्लुकात किन हस्तियों से हैं। शाम हो चुकी थी। गाड़ी पेडर रोड पर हाजी मस्तान के बंगले बैतुल सुरूर पहुंची। बैतुल सुरूर यानी खुशियों का घर। हाजी मस्तान ने जेनाबाई को'सलाम अलैकुम आपा' कहा। जेनाबाई ने भी'वालेकुम सलाम' में जवाब दिया और पूछा मस्तान भाई कैसे हैं आप? हाजी मस्तान ने कहा-'आइए अंदर आइए। ठीक नहीं हैं। तभी तो आपको आज याद किया है।' जेनाबाई ने लगे हाथ पूछा'सब खैरियत तो है। इतना परेशान क्यों दिख रहे हैं।' हाजी मस्तान ने दर्द बयान किया-'आपा मेरी रातों की नींद उड़ी हुई है। सब काम धंधे ठप पड़े हैं। आखिर मैं करूं तो क्या करूं? आइए पहले बैठिए। चाय लेंगी या कॉफी?' जेनाबाई ने पानी मांगा और कहा-'वैसे मैं ये कह रही थी कि अगर काम धंधे ठप पड़े हैं तो ये सिगरेट फूंककर तो चलने वाले नहीं हैं। अभी एक सिगरेट खत्म की और अब दूसरी सुलगा ली। ऐसा लगता है, सिगरेट नहीं तुम खुद जल रहे हो।' हाजी मस्तान ने कहा'तुमने दुरुस्त फरमाया है आपा। मस्तान की जिंदगी धुआं बनकर उड़ी जा रही है। मैं सारे अवैध धंधे छोड़ देना चाहता हूं। क्योंकि, मैंने जयप्रकाश नारायण भाई से वादा किया था। उन्होंने तभी मेरी रिहाई में मदद की। अब मैं वादा पूरा करना चाहता हूं। ये सभी गैरकानूनी काम बंद करके। मैं कई दिन से सोच रहा हूं, कुछ काम करूं, मगर करूं तो क्या?'

उल्लेखनीय है कि हाजी मस्तान को साल 1974 में मीसा के तहत गिरफ्तार किया गया था। वर्ष 1971 में इंदिरा गांधी के समय बना मीसा वो कानून था, जिसके तहत किसी को भी अरेस्ट करके जेल में रखा जा सकता था। वह भी अनिश्चित काल के लिए। बिना वारंट के तलाशी ली जा सकती थी। सामान जब्त किया जा सकता था। तो मस्तान को 90 दिन जेल में रखा गया। इस कानून के तहत जेनाबाई को भी गिरफ्तार किया गया था, बाद में छोड़ दिया गया। अब मस्तान जेल के चक्कर काटकर परेशान हो गया था। इतने मुकदमें हुए कि उसपर कर्ज चढ़ गया था। तो अब वह अपना काम धंधा बदलना चाहता था। इसलिए वह जेनाबाई से मदद मांग रहा था।

मुलाकात के दौरान जेनाबाई से हाजी मस्तान ने कहा-'आपा मेरे ऊपर इतना कर्जा चढ़ गया है कि ऐसे ही रहा तो जिंदगी भर ना उतार पाऊंगा। मेरे पास दो ऑप्शन हैं या तो प्रॉपर्टी का काम करूं या फिर सिनेमा में किस्मत आजमाऊं।' जेनाबाई ने सुझाव दिया'सिनेमा में पैसा लगाना खतरे से खाली नहीं है।' हाजी मस्तान ने कहा कि'मैं प्रॉपर्टी की खरीद फरोख्त के बारे में कई दिन से सोच रहा हूं। और मेरी नजर में एक बड़ी प्रॉपर्टी भी है। मुंबई की बेलासिस रोड पर एक बड़ी प्रॉपर्टी है, वह मिल जाए तो मेरा काम बन जाए। मगर क्या करूं आपा उसपर पहले ही कब्जा है। अगर वो जमीन मिली तो समझो सारा कर्जा उतर जाएगा।' इसपर जेनाबाई ने पूछा'तुम्हें लगता है कि ये जमीन मैं तुम्हें दिला सकती हूं।' हाजी मस्तान ने कहा-'आपा मैं जानता हूं, आप कोई ना कोई जुगाड़ निकाल लेंगी। कोई तो तिकड़मबाजी आपके पास होगी।' जेनाबाई ने कहा'करीम भाई से तुमने बात की इस बारे में? वह भी तो मदद कर सकते हैं।' हाजी मस्तान ने कहा कि'मैंने कुछ टाइम पहले करीम लाला से बात की थी। उसने बोल दिया शायद वो इस बार मदद नहीं कर पाएगा। क्योंकि, जिन लोगों के कब्जे में वह जमीन है वो चिलिया हैं। गुजरात के बनासकांठा जिले के मुसलमान चिलिया। बड़े ही ताकतवर। मेरे कहने पर करीम ने अपने आदमी

वहां भेजे थे। मगर, जब वापस आए तो उनकी हड्डी पसली टूटी थी। ये चिलिया जिसको अपना मान लेते हैं, फिर वो चीज किसी को नहीं देते हैं आपा। अब बताइए क्या करा जाए?' सुनकर जेनाबाई ने ठहाके लगाया'हाहाहहाहाहाहा। तुम हाजी मस्तान ही हो ना। मुझे तो शक हो रहा है। हाजी मस्तान तो ऐसा नहीं था। इतना डरने वाला। आज तुम्हारी हालत तो डोंगरी के किसी आम आदमी जैसी हो गई भाई।' हाजी मस्तान झेंपा'तुम हंस रही हो। यहां मैं परेशान हूं और तुम मेरा मजाक बना रही हो।' जेनाबाई ने कहा'भाई परेशान मत होइए। काम हो जाएगा।' जिन लोगों से अंडरवर्ल्ड डॉन हाजी मस्तान डर गया। उन लोगों की परवाह किए बिना जेनाबाई ने क्यों कहा काम हो जाएगा। आखिर कौन सी ताकत थी जेनाबाई के पास? जमीन हासिल करने के लिए आखिर क्या चाल खेली होगी अंडर व्लर्ड की इस क्वीन ने? उसने कैसे दाऊद इब्राहिम को इस काम में लगाया यह भी जानना दिलचस्प होगा।

....जारी

बांग्लादेशः समुद्री पानी का कहर जिस्म बेचने को मजबूर औरतें

गरीबी और भूख के कारण टूट चुकी कुछ मजबूर औरतों के जिस्म की मंडी में चले जाने की कहानियां तो हमने सुनी हैं, लेकिन बांग्लादेश की महिलाओं को अलग ही झमेलों से दो-चार होना पड़ रहा है। यहां की औरतें किन परिस्थितियों से गुजर रही हैं, जानकर लोगों को बड़ा दुख हो सकता है। हाल ही में सामने आयी एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के दक्षिण-पश्चिम तट पर रहने वाली महिलाओं को समुद्र के पानी की वजह से अपने जिस्म का सौदा करना पड़ रहा है।

भूख और गरीबी के कारण टूट चुकी कुछ औरतों के जिस्म की मंडी में चले जाने की कहानियां तो हमने सुनी हैं, लेकिन बांग्लादेश की महिलाओं को अलग ही झमेलों से दो-चार होना पड़ रहा है। यहां की औरतें किन परिस्थितियों से गुजर रही हैं, जानकर लोगों को बड़ा दुख हो सकता है। हाल ही में सामने आयी एक न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश के दक्षिण-पश्चिम तट पर रहने वाली महिलाओं को समुद्र के पानी की वजह से अपने जिस्म का सौदा करना पड़ रहा है।

दरअसल, ये औरतें समुद्र के लगातार बढ़ते जलस्तर से परेशान हैं। अपना घर चलाने के लिए उन्हें सेक्स वर्कर की जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। इस तट पर रहने वाली सैकड़ों महिलाएं इस काम में लगी हुई हैं। कई तो मानव तस्करी कर यहां लाई गई हैं। यहां रहने वाली महिलाओं का कड़वा सच उस समय सामने आया जब कुछ रिपोर्टर्स इन कोठों पर पहुंचे। सेक्स वर्कर्स ने उन्हें अपना ग्राहक समझ लिया। लेकिन, जब पता चला कि वे रिपोर्टर हैं तो उन्होंने अपनी आपबीती उन्हें सुनाई। एक महिला ने बताया कि वह 15 साल की थी जब समुद्री तूफान की वजह से उसके घर और खेत बर्बाद हो गए। इसके अलावा समुद्र के बढ़े जलस्तर की वजह से मिट्टी का कटाव भी जारी है, जिससे उनका घर खतरे में हैं। इसका फायदा उठाते हुए एक महिला ने उसे कपड़े की फैक्ट्री में नौकरी दिलवाने का वादा किया। लेकिन, उसने जिस्म फरोशी के धंधे में धकेल कर बेच दिया।

रिपोर्टस की मानें तो बांग्लादेश में बनिशंता वेश्यालय काफी पुराना वैश्यालय है, जहां पास के ही बंदरगाह मोंगला बंदरगाह से ग्राहक आते हैं। हैरानी की बात तो ये है कि यहां कई बुजुर्ग महिलाएं भी रहती हैं जो कहीं और नहीं जाना चाहतीं। हालांकि अब वह ये काम नहीं करतीं सिर्फ अन्य महिलाओं के साथ रहती हैं। इन महिलाओं ने इस जगह को अपनी दुनिया मान ली है, लेकिन समुद्री जलस्तर से उनकी यह दुनिया अब खतरे में है। मिट्टी के कटाव और तूफान की वजह से इनके घर डूबने की कगार तक आ गए हैं। सेक्स वर्कर महिलाओं के हवाले से बताया गया है कि वह चाहकर भी कहीं और नहीं जा सकती क्योंकि उन्हें कोई अपनाएगा नहीं। उन्हें यहीं रहकर अपने जिस्म का सौदा कर पैसे कमाने पड़ते हैं। इनमें से ज्यादातर पैसे बाढ़ और तूफान से क्षतिग्रस्त हुए घरों की मरम्मत करने में खर्च हो जाते हैं। यहां तक कि उन्हें कई बार कर्ज भी लेना पड़ता है। समुदाय की मुखिया रजिया बेगम ने बताया कि बंदरगाह की वजह से ही यहां ग्राहक आते हैं। ये जगह और ये काम हमारी जीविका के लिए बहुत जरूरी है।

- श्रीहरि सुदर्शन

पुण्यतिथि 07 अगस्त पर विशेष

गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगौर

गांधी के आलोचक भी मुरीद भी

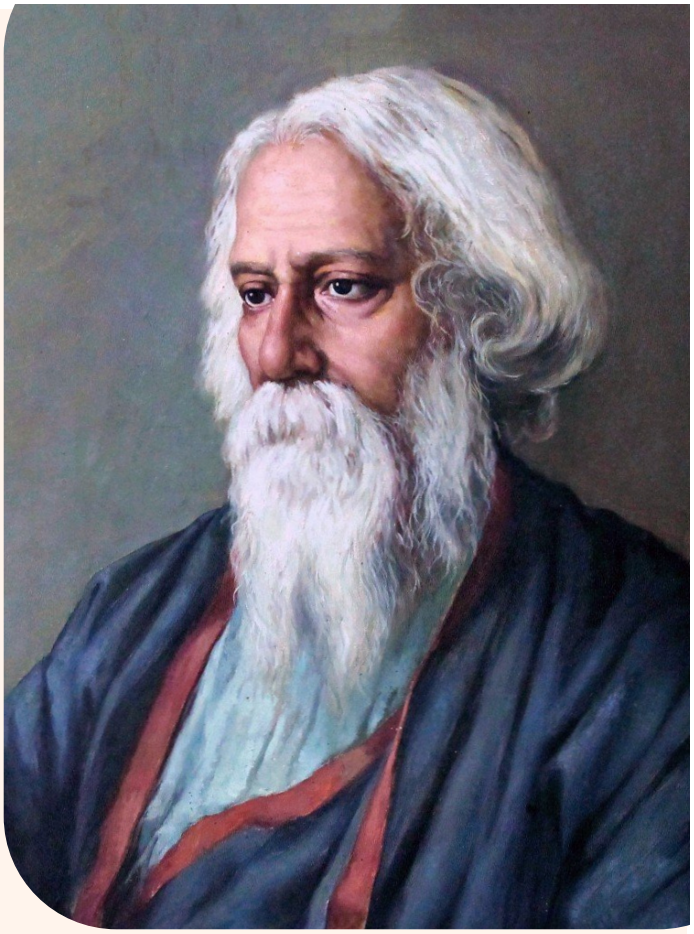

महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का सफल प्रयोग कर रहे थे, तो उन्हें भारत लाने के लिए सीएफ एन्ड्र्यूज को अफ्रीका भेजने वाले गोपाल कृष्ण गोखले और रवींद्रनाथ टैगोर ही थे। भारत आने के बाद गांधी ने भारतीय जनमानस को एकदम नीचे उतरकर समझने की कोशिश की। आगे का रास्ता उन्होंने खुद ही बनाना शुरू किया। टैगौर जैसे कवि और दार्शनिक तक गांधी के बहुत सारे तरीकों और निर्णयों को शुरू-शुरू में ठीक से समझ नहीं पाए उन्होंने ऐसे अवसरों पर कड़े शब्दों में गांधी के उन निर्णयों की आलोचना की।

प्रसन्नजीत साहा

हर साल 10 मार्च का दिन शांतिनिकेतन में'गांधी दिवस' के बतौर मनाया जाता था। वर्ष 1915 में इसी महीने गांधी और टैगोर की पहली मुलाकात शांति निकेतन में हुई थी। दक्षिण अफ्रीका में अपने आश्रम जीवन के अभ्यस्त हो चुके गांधी अपना सारा काम खुद अपने ही हाथों से करते थे। सो, शांति निकेतन में भी जब उन्होंने अपना कमरा और बिस्तर खुद ही साफ किया और अपने कपड़े और बर्तन भी खुद ही धोए तो यह देखकर शांति निकेतन के छात्र अपनी परावलंबिता पर बहुत शर्मिंदा हुए थे। शांतिनिकेतन में तो छात्रों को नौकर-चाकर, रसोइये और सफाईकर्मियों की आदत पड़ चुकी थी। इसलिए गांधी से प्रभावित होते हुए भी वे उनके इस अनुशासन को अपनाने के बारे में बहुत चिंतित हो गए। गांधी को यह बात समझते देर नहीं लगी। इसलिए उन्होंने सभी छात्र-छात्राओं को आत्मनिर्भरता का प्रशिक्षण देने के लिए 10 मार्च का दिन मुकर्रर किया।

शुरू-शुरू में तो छात्रों ने इसमें उत्साह से भाग लिया, लेकिन गांधी के जाते ही सबकुछ पुराने ढर्रे पर आ गया। फिर भी हर साल 10 मार्च को सभी कर्मचारियों को छुट्टी दे दी जाती थी और शांति निकेतन में रहने वाले सभी लोग अपना सारा काम खुद ही करते थे। इसे ही उन्होंने'गांधी दिवस' का नाम दिया था। महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह का सफल प्रयोग कर रहे थे, तो उन्हें भारत लाने के लिए सीएफ एन्ड्र्यूज को अफ्रीका भेजने वाले गोपाल कृष्ण गोखले और रवींद्रनाथ टैगोर ही थे। भारत आने के बाद गांधी ने भारतीय जनमानस को एकदम नीचे उतरकर समझने की कोशिश की। आगे का रास्ता उन्होंने खुद ही बनाना शुरू किया। टैगौर जैसे कवि और दार्शनिक तक गांधी के बहुत सारे तरीकों और निर्णयों को शुरू-शुरू में ठीक से समझ नहीं पाए उन्होंने ऐसे अवसरों पर कड़े शब्दों में गांधी के उन निर्णयों की आलोचना की। लेकिन, गांधी ने अपने स्वभाव के अनुरूप ही कभी भी उनपर कोई तीखी प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन मीठे स्पष्टीकरण जरूर देते रहे। आज हम ऐसे ही कुछ प्रसंगों का जिक्र करेंगे जब टैगोर ने सैद्धांतिक स्तर पर गांधी के निर्णयों की आलोचना की, हालांकि दोनों के बीच व्यक्तिगत आत्मीयता में कभी कमी नहीं आई।

गांधीजी को'वंदे मातरम' के नारे में कोई समस्या नजर नहीं आती थी, उन्होंने एकाधिक अवसरों पर इसकी सराहना भी की थी। लेकिन, टैगोर इस नारे के एकदम खिलाफ थे। टैगोर बंगाली थे और उन्होंने बंगाल की कालीपूजा में'मां' का एक हिंसक स्वरूप भी देखा था, जहां मां की जय-जयकार करते हुए वीभत्स रूप से बकरों की खूनी बलि दी जाती थी। काका कालेलकर ने लिखा है कि टैगोर को यह भी लगता था कि'शक्ति' की उपासना स्वतंत्रता के राजनीतिक संघर्ष को हिंसा और आतंक के रास्ते पर बढ़ाने में भी योगदान दे रहा था। ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचार के खिलाफ जिस समय गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, उस दौरान टैगोर यूरोप के दौरे पर थे और पूरब तथा पश्चिम की आध्यात्मिक एकता के सूत्र तलाश रहे थे। टैगोर को गांधी का यह संघर्षकारी रवैया खटका

और उन्होंने सीएफ एन्ड्र्यूज को पत्र लिखकर इसकी आलोचना की थी और बाद में तो खुलकर सार्वजनिक रूप से वे असहयोग आंदोलन के विरोध में आ गए। टैगोर के मुताबिक असहयोग एक नकारवादी विचार था और इससे मानवता में विश्वास की नीति की भी अनदेखी होती थी। टैगोर ने असहयोग को भी'एक प्रकार की हिंसा' करार दिया था।

टैगोर के इस रवैये के जवाब में महात्मा गांधी ने एक जून 1921 के'यंग इंडिया' में एक लंबा लेख लिखा जिसका शीर्षक था-'कविवर की चिंता'। गांधी ने लिखा-'मेरी समझ में रवींद्र बाबू को असहयोग आंदोलन के अभावात्मक या खंडनात्मक पक्ष से चौंकने की कोई जरूरत नहीं थी। हम लोगों ने'नहीं' कहने की शक्ति बिल्कुल गंवा दी है। सरकार के किसी काम में'नहीं' कहना पाप और अभक्ति गिना जाने लगा था। हर एक किसान जानता है कि फसल बढ़ते रहने की अवधि में भी खुरपी का उपयोग करते रहना जरूरी है।' टैगोर ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार और उन्हें जलाने की गांधी की मुहिम का भी विरोध किया था। उन्होंने इसे ठेठ अर्थशास्त्रीय नजरिए से देखा और कहा कि चूंकि भारत की एक बड़ी आबादी के पास पहनने को वस्त्र नहीं हैं, इसलिए उसे जो भी वस्त्र मिलता है उसे अपनाना चाहिए। जबकि गांधी इसे न केवल अपने ही अर्थशास्त्रीय नजरिए से देख रहे थे, बल्कि इसे आत्म-शुद्धिकरण का तरीका मान बैठे थे। इतना तक कि अपने राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा कस्तूरबा को उपहार में दिए गए हाथ से बुनी गई विदेशी सूत की साड़ी तक उन्होंने अपने हाथों से जला दी थी।

1934 में बिहार में भयानक भूकंप आया और बड़ी तबाही हुई। महात्मा गांधी ने तमिलनाडु में एक सार्वजनिक सभा में कहा कि यह दलितों के प्रति छुआछूत के पाप का ईश्वरीय दंड है।

टैगोर ने गांधी के इस वक्तव्य को घोर अंधविश्वास का नमूना करार दिया। उन्होंने भूकंप के पीछे के इस तर्क को अवैज्ञानिक करार दिया और एक व्यंग्यपरक लेख लिखा जिसे स्वयं महात्मा गांधी ने 16 फरवरी, 1934 को अपने जवाब के साथ'यंग इंडिया' में छापा। टैगोर ने लिखा था कि इस तरह का तर्क तो महात्माजी के विरोधियों को ही शोभा देता है। दरअसल, गांधी के इस बयान के बाद सनातनियों की ओर से भी तरह-तरह के बयान आने शुरू हो गए थे। किसी सनातनी ने कहा कि देश में जो सूखे और अकाल पड़ते हैं वे दरअसल गांधी के छूआछूत-विरोधी आंदोलनों के ही दुष्परिणाम हैं। किसी ने कहा कि इससे पहले कि भूकंप के लिए गांधीजी के आंदोलनों को दोषी ठहराया जाता, उन्होंने सवर्णों को इसके लिए दोषी ठहराकर बढ़त बना ली है।

दूसरी ओर गांधी जी ने टैगोर का आलोचनापूर्ण आलेख तो यंग इंडिया में छापा ही, साथ ही इसका जवाबी लेख भी छापा जिसका शीर्षक था-'अंधविश्वास बनाम श्रद्धा'। इसमें उन्होंने लिखा -''मेरे इस मंतव्य पर कि बिहार के संकट का संबंध अस्पृश्यता के पाप से है, गुरुदेव ने अभी-अभी जो कुछ कहा है उससे हमारे पारस्परिक स्नेह में कोई अंतर नहीं आ सकता। उनके प्रति जो मेरे मन में अगाध सम्मान है उसके कारण यह स्वाभाविक है कि मैं अन्य आलोचकों की अपेक्षा उनकी आलोचना की ओर और ज्यादा तत्परतापूर्वक ध्यान दूंगा। किंतु उनके वक्तव्य को तीन बार पढ़ जाने के बावजूद मैं इन स्तंभों में लिखी अपनी बातों पर कायम हूं। बड़े-से-बड़े वैज्ञानिक या दार्शनिक का ज्ञान भी धूल के कण जितना ही है। गुरुदेव की तरह मैं भी यह मानता हूं कि अटल विधान को कोई नहीं बदल सकता। क्योंकि ईश्वर और

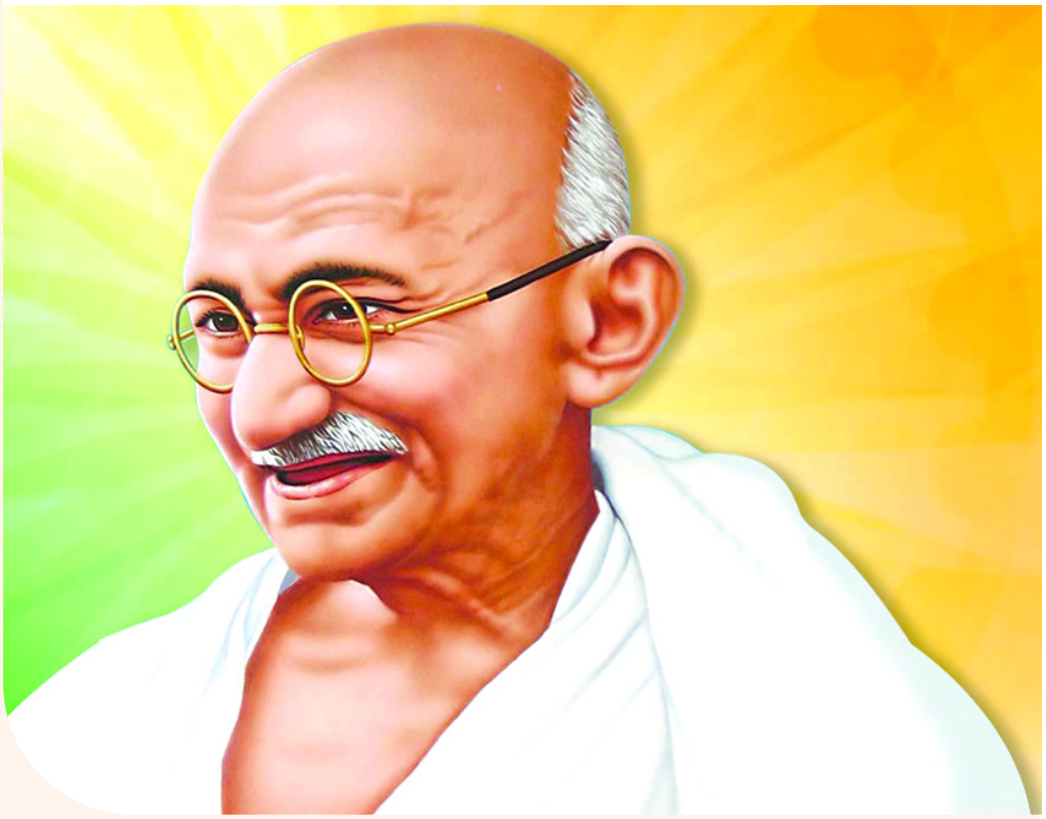

उसका विधान एक ही है। किंतु मुझे स्वीकार करना चाहिए कि उस नियम को या उन नियमों को हम पूरी तरह से नहीं जानते, और जो चीज हमें विपत्ति-सी लगती है, वह वैसी इसलिए लगती है कि हम विश्व-नियमों को भली-भांति नहीं जानते। बेशक, सनातनियों को भी यह कहने का पूरा अधिकार है कि यह अस्पृश्यता के विरुद्ध मेरे प्रचार करने के अपराध का दंड था। मैं गुरुदेव की तरह यह नहीं मानता कि हमारे अपने पाप और भूलें चाहे जितनी बड़ी हों, उनमें इतनी शक्ति नहीं है कि वे सृष्टि के ढांचे को नष्ट-भ्रष्ट कर दें। इसके विपरीत, मेरा विश्वास यह है कि हमारे पापों में उस ढांचे को नष्ट कर देने की इतनी शक्ति है जितनी किसी निरे प्राकृतिक व्यापार में नहीं है।''

टैगोर ने अंग्रेजी भाषा में शिक्षण के प्रति गांधीजी की चेतावनी का भी विरोध किया था। 27 अप्रैल, 1921 के'यंग इंडिया' में गांधीजी ने अंग्रेजी शिक्षा पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि''मेरी यह सोची-समझी राय है कि अंग्रेजी शिक्षा जिस ढंग से दी गई है उसने अंग्रेजी पढ़े-लिखे भारतीयों को नामर्द बना दिया है। उसने भारतीय विद्यार्थियों के दिमागों पर एक भारी बोझ डाल दिया है और हम लोगों को नकलची बना दिया है। राममोहन राय को यदि अंग्रेजी में सोचने और अपने विचार व्यक्त करने का झंझट नहीं होता तो वे और भी बड़े सुधारक बन सकते थे। यही बाधा यदि लोकमान्य तिलक के आड़े नहीं आती तो वे और भी बड़े विचारक सिद्ध होते। चैतन्य, कबीर, नानक, गुरु गोविंदसिंह, शिवाजी और प्रताप हमारे राममोहन राय और तिलक से कहीं बड़े थे।''

गांधीजी की यह बात टैगोर को नागवार गुजरी। अपने यूरोप दौरे पर ही उन्होंने इसके विरोध में शांति निकेतन के व्यवस्थापक को एक जोरदार चिट्ठी लिखी, जो बाद में इस शीर्षक से छपी -'राजा राममोहन राय को बौना मत ठहराइए'। टैगोर ने इसमें लिखा था -''आधुनिक शिक्षा को तुच्छ ठहराने के अपने अंध-आवेश में महात्मा गांधी ने राममोहन राय जैसे आधुनिक भारत के महान व्यक्तित्वों का जो अपमान किया है, मैं उसका कड़ा विरोध करता हूं। यह दिखाता है कि वे अपने सिद्धांतों के प्रति आत्ममुग्ध होते जा रहे हैं जो कि अहंकार का ही एक खतरनाक रूप है और महान से महान लोग भी कभी-कभी इसका शिकार हो जाते हैं।''

गांधी ने जब यह पढ़ा तो उन्होंने भी इसका जवाब दिया। दोनों ने काफी तार्किक बहसें की, लेकिन इन बहसों से दोनों में एक-दूसरे के लिए सम्मान कभी कम नहीं हुआ। 'यंग इंडिया' में एक जून 1921 को गांधी जी ने लिखा-'मुझे यह देखकर दुख हुआ कि डॉ ठाकुर (टैगोर) का वह पत्र तथ्यों को जाने बिना गुस्से में लिखा गया है। इस बात पर भी वे रुष्ट हुए हैं कि मैंने महिलाओं को अंग्रेजी की पढ़ाई बंद करने की सलाह दी है। अंग्रेजी की पढ़ाई बंद करने के मैंने जो कारण दिए हैं कवि ने उन्हें अपने लिए मान लिया। दूसरी ओर गांधीजी द्वारा चरखा और खादी के कथित महिमामंडन की आलोचना करते हुए टैगोर ने सितंबर, 1925 में एक लंबा लेख लिखा था जिसका शीर्षक था-'दी कल्ट ऑफ चरखा'। महात्मा गांधी ने पांच नवंबर, 1925 के'यंग इंडिया' में'कवि-गुरु और चरखा' शीर्षक से एक लेख लिखकर उन आलोचनाओं का जवाब दिया था। गांधीजी ने आगे लिखा-'सच तो यह है कि कवि-गुरु की आलोचना कवि सुलभ स्वच्छन्दता का एक नमूना है और इसलिए यदि कोई उसे शब्दशः पकड़कर चलेगा तो किसी भी क्षण उसकी स्थिति बड़ी अटपटी बन सकती है। इस तरह कई अवसरों पर और कई प्रश्नों पर गांधीजी और टैगोर के बीच एक मीठा और आलोचनात्मक संवाद चलता रहा। लेकिन कई अन्य अवसरों पर दोनों ने एक-दूसरे के बारे में इतनी भावपूर्ण बातें कही हैं जिन्हें पढ़कर एक-दूसरे के प्रति उनके अगाध सम्मान का पता चलता है।

विश्व आदिवासी दिवस 9 अगस्त पर विशेष

आदिवासियों को चाहिए इन सवालों के जवाब

अमित राजा
(लेखक **इंडियन पंच** 'हिन्दी दैनिक' के कार्यकारी संपादक हैं)

आदिवासियों की चिंता जताने वाले सियासत में हर कहीं मिल जायेंगे। बेहतर भविष्य बना चुके किसी खलको, तिर्की या टुडू की तरक्की का इन्हें क्रेडिट चाहिए। लेकिन, भूख और रोग से पीड़ित आदिवासी समुदाय की बदहाली का बोझ इन्हें अपने कंधों पर नहीं ढोना है। आखिर क्यों? आदिवासियों को अब इन सवालों का जवाब मिलना चाहिए। आदिवासी शब्द सामने आते ही छल-प्रपंच, नकारात्मकता से मुक्त और बदलावकारी आंदोलनों के कर्मठ लड़ाके और संघर्षशील इंसान की छवि उभरती है। मगर, वह हर कहीं छला गया।

आदिवासी युवकों किस्टा गौड़ और भूमैया को फांसी की सजा माफ कराने की मांग पर प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से बातचीत के दौरान कुछ ही दिनों पूर्व लखनऊ की एक युवती शमीम रहमानी की मौत की सजा समाप्त करने का उदाहरण दिया था। एक प्रेम त्रिकोण की वजह से शमीम रहमानी ने लखनऊ के एक युवा डॉक्टर गौतम की गोली मार कर हत्या कर दी थी। राष्ट्रपति से जब इसका जिक्र किया गया तो वह बौखला गये। उनका जवाब था कि शमीम रहमानी एक नवाब खानदान की एक खानदानी लड़की थी और उससे एक चूक हो गयी। जबकि आदिवासी किस्टा गौड़ और भूमैया उस तबके से आते हैं जो जरायमपेशा है, जिसका काम ही अपराध करना है। ऐसे लोगों की तुलना शमीम रहमानी से नहीं हो सकती है। इनकी सजा किसी भी हालत में माफ नहीं होगी। कम्युनिस्ट पार्टी के दोनों आदिवासी युवकों को 1 दिसंबर 1975 को फांसी पर लटका दिया गया।

आदिवासी शब्द सामने आते ही छल-प्रपंच, नकारात्मकता से मुक्त और बदलावकारी आंदोलनों के कर्मठ लड़ाके और संघर्षशील इंसान की छवि उभरती है। मगर, वह हर कहीं छला गया। उसके आंदोलन कई बार बेचे गये। जल, जंगल, जमीन पर गांव-समाज के अधिकार की मांग तो पूरी नहीं हुई ऊपर से वह घर से भी बेदखल हुआ। आदिवासी मतलब जिनका चलना नृत्य व बोलना संगीत है। आदिवासियों का यह दर्शन उनके पूरे जीवन को ही उत्सव बना देता है। जहां, सिर्फ आज की चिंता होती है।

1970 दशक में तत्कालीन एक राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तो आदिवासियों को ही अपराधी बता दिया था। बात वर्ष 1974 की है। आंध्र प्रदेश के दो आदिवासी युवकों किस्टा गौड़ और भूमैया को फांसी की सजा सुनायी गयी थी। उन पर आरोप था कि उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में किसी जमींदार की हत्या की साजिश में हिस्सा लिया था। उन्हें फांसी की सजा सुनायी गयी थी। तब दिल्ली में हिन्दी, अंग्रेजी और पंजाबी के कई लेखकों-बुद्धिजीवियों ने जॉर्ज फर्नांडीस की अध्यक्षता में एक अभियान समिति गठित की थी। इस समिति के सदस्यों ने फांसी की सजा रद्द करने की मांग पर बोट क्लब पर रात भर धरना दिया था। समिति का एक प्रतिनिधिमंडल तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से मिला और मांगें रखी।

विश्व आदिवासी दिवस

उसके आंदोलन कई बार बेचे गये। जल, जंगल, जमीन पर गांव-समाज के अधिकार की मांग तो पूरी नहीं हुई ऊपर से वह घर से भी बेदखल हुआ। आदिवासी मतलब जिनका चलना नृत्य व बोलना संगीत है। आदिवासियों का यह दर्शन उनके पूरे जीवन को ही उत्सव बना देता है। जहां, सिर्फ आज की चिंता होती है। न तो वे बीते कल में झांकते हैं और न आने वाले कल की फिक्र में उत्सव सरीखे अपने जीवन के आनंद को कम करते हैं।

दरअसल, आदिवासी कोई जाति नहीं, एक समृद्ध संस्कृति और पद्धति का नाम है। ठीक वैसे जैसे मार्क्सवाद या वामपंथियों के कामकाज करने का तरीका है। लेकिन, जिस झारखंड का निर्माण ही आदिवासियों की मुश्किलों का निदान खोजने के लिए हुआ, उस झारखंड की राजनीति आज आदिवासी मुखी न होकर सत्ता मुखी हो गयी है। जल, जंगल, जमीन छीने जाने के खतरे से मुक्ति का मार्ग आदिवासियों के जीवन और उनकी संस्कृति में ही अंतर्निहित है। यह मार्ग बिरसा, तिलका, सिद्धु-कान्हू के विचारों से होकर ही गुजरेगा। लेकिन, आज अंबेदकरवादी आदिवासियों के सवाल उठा रहे हैं। अगर आदिवासियों ने अंबेदकरवादियों का नेतृत्व स्वीकार कर लिया तो वे फिर से ठगे जायेंगे।

अंबेदकर का विचार और बिरसा मुंडा, तिलका मांझी या सिद्धु-कान्हू का रास्ता जुदा-जुदा है। अंग्रेजों के खिलाफ लिखने और उनकी आलोचना के बाद अंबेदकर अंग्रेजों की सत्ता में शामिल हो गये। भारत की गुलामी का विरोध नहीं किया। जबकि बिरसा, तिलका, सिद्धु-कान्हू ने अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी। लड़े। अंग्रेजों के साथ सत्ता की थाली में खीर नहीं खाया। बिरसा, तिलका, सिद्धु-कान्हू के समकालीन भी नहीं हैं अंबेदकर। अंबेदकर के समकालीन तो जयपाल सिंह मुंडा हैं। मगर, जयपाल सिंह मुंडा लगभग भुला ही दिये गये हैं। जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान में आदिवासियों को दलितों के बराबर अधिकार दिलाने का संघर्ष किया। लेकिन, अंबेदकर की जिद की वजह से संविधान में आदिवासी शब्द शामिल नहीं हो सका।

संविधान में दलित हैं, मगर आदिवासी नहीं

संविधान में कहीं भी आदिवासी शब्द नहीं है। दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है कि आदिवासी की लाक्षणिकता अनुसूचित जनजाति में नहीं है। इसलिए कहा जा सकता है कि संविधान में आदिवासी शब्द ना डाल कर आदिवासियों से छल किया गया है। संविधान में आदिवासियों को जो भी हक मिले, वह केवल एक आदिवासी नेता जयपाल सिंह मुंडा की ही देन हैं।

> अंबेदकर का विचार और बिरसा मुंडा, तिलका मांझी या सिद्धु-कान्हू का रास्ता जुदा-जुदा है। अंग्रेजों के खिलाफ लिखने और उनकी आलोचना के बाद अंबेदकर अंग्रेजों की सत्ता में शामिल हो गये। भारत की गुलामी का विरोध नहीं किया। जबकि बिरसा, तिलका, सिद्धु-कान्हू ने अंग्रेजी सत्ता को चुनौती दी। लड़े। अंग्रेजों के साथ सत्ता की थाली में खीर नहीं खाया। बिरसा, तिलका, सिद्धु-कान्हू के समकालीन भी नहीं हैं अंबेदकर। अंबेदकर के समकालीन तो जयपाल सिंह मुंडा हैं। मगर, जयपाल सिंह मुंडा लगभग भुला ही दिये गये हैं। जयपाल सिंह मुंडा ने संविधान में आदिवासियों को दलितों के बराबर अधिकार दिलाने का संघर्ष किया। लेकिन, अंबेदकर की जिद की वजह से संविधान में आदिवासी शब्द शामिल नहीं हो सका।

संविधान सभा में आदिवासी मुद्दों पर डॉ आंबेडकर और जयपाल सिंह मुंडा के बीच काफी द्वंद्व, तकरार और मतभेद थे। इस मुद्दे पर जयपाल सिंह मुंडा अकेले पड़ गये और उन्हें संविधान सभा में साथ देने वाला कोई भी नहीं मिला। वहीं इस परिस्थिति का फायदा उठाकर डॉ आंबेडकर ने आदिवासी मुद्दों की कीमत पर दलित अधिकारों को आगे रखकर संविधान सभा के सदस्यों को अपने पक्ष में कर लिया।

दलितों के सवाल और आदिवासियों का मसला भी अलग-अलग है। इसलिए एक मंच पर दोनों के सवाल रखे जाने पर आदिवासी फिर छले जाएंगे। छुआ-छुत के दौर में दलितों के भीतर मंदिर प्रवेश को लेकर बड़ी बेचैनी थी। जबकि आदिवासियों का ध्यान इस मसले पर गया ही नहीं। आदिवासी परिवारों में ही आपको धर्म के लिहाज से लघु भारत का दर्शन हो जाएगा। पांच सदस्यों के आदिवासी परिवार में इसाई, सरना और हिन्दू भी दिख जाएंगे। इसलिए जातिवाद की राजनीति आदिवासियों को पचेगी नहीं। हिन्दू धर्म से पलायन के लिए पहले अंबेदकर ने इस्लाम पर विचार किया और बाद में वे बौद्ध बन गये। मगर, आदिवासी प्रकृति पूजक हैं और वे वामपंथियों-नक्सलियों की तरह बिना किसी धर्म के भी रह सकते हैं। अंबेदकरवादियों ने दलितों को धर्म के बिना खड़े रहना नहीं सिखाया। अंबेदकरवादी जातिवादी सियासत को आदर्श राजनीति का प्रतिमान मानते हैं। जबकि आदिवासी गांव-समाज को समुदाय बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ यही तरीका अति वामपंथियों या संसदीय वामपंथ का रहा है। इसके उलट जातीय राजनीति गांव-समाज को एक कम्युन बनाने की जगह इसे एक अलगाववादी, रुग्ण और विकलांग समाज के ताने-बाने से युक्त करती है।

कभी अपराधी के पक्ष में खड़े नहीं हुए आदिवासी

आदिवासी व्यवहारिक भी होते हैं और सकारात्मक भी। आदिवासियों ने अपराध या भ्रष्टाचार के मामले में किसी आदिवासी को हुई सजा पर कभी सवाल नहीं उठाया। जबकि लालू प्रसाद यादव या अन्य किसी जातिवादी नेता को जब भी अदालत ने सजा सुनायी है, अंबेदकरवादी इसका विरोध करने से नहीं चुके। दलित-पिछड़े आरोपी रहे तो अदालत में मामले की सुनवाई के लिए अंबेदकरवादियों ने दलित या पिछड़ा समुदाय से ही जज होने की अनिवार्यता बता दी। वे पूरी न्याय व्यवस्था को ही ब्राहम्णवादी-मनुवादी घोषित कर देते हैं। यही हालत रही तो कल सेक्शन 377 मामले की सुनवाई में किन्नर जज की मांग भी उठ सकती है।

विश्व आदिवासी दिवस

आदिवासियों ने कभी अपने समुदाय के अपराधी का समर्थन नहीं किया है। लेकिन, आजाद भारत में 1970 दशक में तत्कालीन एक राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने तो आदिवासियों को ही अपराधी बता दिया था। बात वर्ष 1974 की है। आंध्र प्रदेश के दो आदिवासी युवकों किस्टा गौड़ और भूमैया को फांसी की सजा सुनायी गयी थी। उन पर आरोप था कि उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में किसी जमींदार की हत्या की साजिश में हिस्सा लिया था। उन्हें फांसी की सजा सुनायी गयी थी। तब दिल्ली में हिन्दी, अंग्रेजी और पंजाबी के कई लेखकों-बुद्धिजीवियों ने जॉर्ज फर्नांडीस की अध्यक्षता में एक अभियान समिति गठित की थी। इस समिति के सदस्यों ने फांसी की सजा रद्द करने की मांग पर बोट क्लब पर रात भर धरना दिया था। समिति का एक प्रतिनिधिमंडल तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से मिला और मांगें रखी। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने राष्ट्रपति से बातचीत के दौरान कुछ ही दिनों पूर्व लखनऊ की एक युवती शमीम रहमानी की मौत की सजा समाप्त करने का उदाहरण देते हुए आदिवासी कम्युनिस्ट लड़ाके की फांसी की सजा रद्द करने की मांग की। एक प्रेम त्रिकोण की वजह से शमीम रहमानी ने लखनऊ के एक युवा डॉक्टर गौतम की गोली मार कर हत्या कर दी थी। राष्ट्रपति से जब इसका जिक्र किया गया तो वह बौखला गये। उनका जवाब था कि शमीम रहमानी एक नवाब खानदान की एक खानदानी लड़की थी और उससे एक चूक हो गयी। जबकि आदिवासी किस्टा गौड़ और भूमैया उस तबके से आते हैं जो जरायमपेशा है, जिसका काम ही अपराध करना है। ऐसे लोगों की तुलना शमीम रहमानी से नहीं हो सकती है। इनकी सजा किसी भी हालत में माफ नहीं होगी। कम्युनिस्ट पार्टी के दोनों आदिवासी युवकों को 1 दिसंबर 1975 को फांसी पर लटका दिया गया। आजाद भारत के इतिहास में राजनीतिक बंदियों को फांसी पर लटकाने की यह पहली घटना थी। इस घटना से भारतीय गणराज्य के एक राष्ट्रपति की सोच व्यक्त हुई, लेकिन वामदलों ने सिर्फ तुष्टीकरण के कारण इस सोच पर कोई चोट नहीं किया।

'हरा' नहीं'लाल' था बिरसा मुंडा का झंडा

झारखंड समेत पूरे देश के नायक माने जाने वाले बिरसा मुंडा का झंडा'हरा' नहीं'लाल' था। मार्क्सवादी चिंतक और झामुमो व मार्क्सवादी समन्यवय समिति के संस्थापक स्व. एके राय ने एक साक्षात्कार में मुझे बताया था कि बिरसा मुंडा का झंडा लाल था। वे दो झंडे रखा करते थे। लाल और सफेद। लाल झंडा संघर्ष का प्रतीक था तो सफेद झंडा आदिवासी शुद्धता का। जो हो, आदिवासियों का मूल प्रश्न आज भी देश भर के राजनीतिक एजेंडे से गायब है। आदिवासियों का नेतृत्व कैसा हो, इसे लेकर स्पष्ट राय तक नहीं है। साजिश के तहत आदिवासी प्रश्न को दलितों के सवालों से जोड़ दिया जा रहा है। जेएनयू में बापसा (बिरसा-अंबेदकर-फूले स्टूडेंट्स एसोसिएशन) के गठन के समय भी इस तरह की चिंता जाहिर की गयी थी। लेकिन, आदिवासियों को बड़ी चतुराई से भ्रमजाल में फांसे रखा गया। लिहाजा,'बापसा' के नेतृत्व में जेएनयू जैसे अकादमिक संस्थान में आदिवासियों के मुख्य सवाल विस्थापन, जल-जंगल-जमीन के मुद्दे पर बौद्धिक विमर्श की जगह महिषासुर का जयंती-शहादत समारोह ही आयोजित हुआ।

> अंबेदकर की रचना'जाति का उन्मूलन' में वह कहीं भी नहीं बताते कि जाति का उन्मूलन कैसे होगा। उल्टे अंत में वह इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जाति का उन्मूलन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ब्राह्मण ऐसा होने नहीं देंगे। जाहिर है, ब्राह्मणों से इजाजत लेकर जाति का खात्मा नहीं हो सकता है। अंबेडकर अंत में बौद्ध धर्म को अपना लेने में ही दलितों की मुक्ति देख रहे थे। लेकिन, इतिहास ने प्रदर्शित कर दिया है कि बौद्ध धर्म अपनाने वाले दलित नवबौद्ध कहलाये और उस धर्म में भी जाति का प्रवेश हो गया। वहां भी उनकी स्थिति दलितों जैसी ही बनी रही। इसलिए आदिवासियों को बिरसा, तिलका को ही आगे कर राजनीति करनी होगी और भूल से विपरीत विचारधाराओं संग मंच साझा करने से बचना होगा।

अंबेदकर की रचना'जाति का उन्मूलन' में वह कहीं भी नहीं बताते कि जाति का उन्मूलन कैसे होगा। उल्टे अंत में वह इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जाति का उन्मूलन हो ही नहीं सकता, क्योंकि ब्राह्मण ऐसा होने नहीं देंगे। जाहिर है, ब्राह्मणों से इजाजत लेकर जाति का खात्मा नहीं हो सकता है। अंबेडकर अंत में बौद्ध धर्म को अपना लेने में ही दलितों की मुक्ति देख रहे थे। लेकिन, इतिहास ने प्रदर्शित कर दिया है कि बौद्ध धर्म अपनाने वाले दलित नवबौद्ध कहलाये और उस धर्म में भी जाति का प्रवेश हो गया। वहां भी उनकी स्थिति दलितों जैसी ही बनी रही। इसलिए आदिवासियों को बिरसा, तिलका को ही आगे कर राजनीति करनी होगी और भूल से विपरीत विचारधाराओं संग मंच साझा करने से बचना होगा।

दलितों को मंदिर प्रवेश मिल जाने के बाद अंबेदकरवादियों ने हिन्दू धर्म के मिथकों को सामने लाने की कोशिश की और बाद में एक तरह के मिथक का ही पक्षपोषण किया। उनके लिए राष्ट्रीय समस्या ब्राह्मणवाद है। इसका विरोध करते हुए वे एक प्रति संस्कृति के निर्माण और समानांतर परंपरा के संधान की कोशिश करते हैं। मिथकों की पुनर्व्याख्या करते-करते वे मिथकों को ही हथियार बना लेते हैं। महिषासुर को नायक बनाने वाले ये लोग मिथकों का ऐसा ही प्रयोग करते हैं। जबकि आदिवासियों के लिए जंगल, पानी और जमीन पर समुदाय की मिल्कियत ही मुख्य मुद्दा है। आज के अंबेदकरवादी कहते हैं कि दलित ही दलित का दर्द समझ सकता है। दलितों पर खूब स्याही और कागज खर्चने वाले मुंशी प्रेमचंद के साहित्य को वे दलित साहित्य मानने से इंकार कर देते हैं। इनका मानना है कि दलितों की मुक्ति के लिए बोलने का अधिकार भी गैर दलितों के पास नहीं है। जबकि वास्तव में दलित अस्मिता को स्थापित करने के सिवा अंबेडकर के पास दलित मुक्ति का कोई रास्ता नहीं था। सिर्फ भावनाओं के धरातल पर और दलित आबादी के तुष्टीकरण के लिए ही काम हुआ।

विश्व आदिवासी दिवस

दूसरी ओर आदिवासियों के साथ ऐसी बात नहीं है। गैर आदिवासी महाश्वेता देवी, अमर कुमार सिंह, डॉ बीडी शर्मा, डॉ कुमार सुरेश सिंह के शोधों को उन्होंने सराहा। इसे आदिवासी साहित्य का नाम दिया। आदिवासियों का यह बौद्धिक नजरिया मार्क्सवादी है। आदिवासियों का जीवन स्त्री-पुरूष और प्रकृति-पशु के बिना संपूर्ण नहीं होता। इंसानों के साथ वे पशुओं की भी चिंता करते हैं। एक समय ऐसा था जब आदिवासी गांव का कोई व्यक्ति जंगल से कटहल तोड़ लाता तो गांव के प्रधान उसे दंडित करते थे। उनका मानना था कि जंगल के फलों पर जगली जानवरों का अधिकार है। जंगल से फल तोड़ कर ले आने पर जंगली पशुओं को भोजन नहीं मिलेगा और वे गांव में भोजन की खोज के लिए दाखिल होंगे। पशुओं के लिए भी भोजन की चिंता करने का मिजाज आदिवासियों को महा मार्क्सवादी बनाता है। आज हाथी गांव में घुस रहे हैं। तबाही मच रही है तो सिर्फ इसलिए कि आदिवासियों की संस्कृति और उनकी समाज-व्यवस्था ध्वस्त कर दी गयी।

आज जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं। जिसका सीधा नुकसान आदिवासियों को हो रहा है। क्योंकि जंगलों के फल, पत्ते, सूखी लकड़ियों पर आदिवासियों का हक होता है, लेकिन जंगल खत्म होने के साथ ये चीजें उनके हाथ से निकल जाती हैं। जबकि, जंगल बचाने का आंदोलन नक्सलियों या वामपंथी दलों को चलाते तो देखा गया है, मगर अंबेदकरवादी संगठन महिषासुर जयंती या पुण्यतिथि मनाने और आरक्षण के पक्ष में आयोजित कार्यक्रमों में ही अपनी उर्जा लगा देते हैं।

निश्छल पशु पेट भरने के बाद दोबारा शिकार तबतक नहीं करते जबतक कि दोबारा उन्हें भूख नहीं लगती। उसी तरह आदिवासी आज में जीते हैं। भ्रष्ट नहीं होते। जरूरत पड़ने पर ही भोजन और संपत्ति का जुगाड़ करते हैं। इसे गलत तरीकों से जुटाते नहीं। भ्रष्टाचार के दोषी या आरोपी कुछ आदिवासी ने कुछ गलत किया है तो इसलिए कि वे बाहरी संस्कृतियों के संक्रमण में आ गये। भ्रष्टाचार के आरोपी मधु कोड़ा सरीखे आदिवासी नेताओं के पक्ष में आदिवासियों को बोलते नहीं देखा जाता है।

-बुनियादी तौर पर किसके करीब हैं आदिवासी?

जंगलों और सुदूर गांवों में रहने वाले आदिवासियों की समाज व्यवस्था साम्यवाद से मिलती-जुलती रही है। आदिवासी ही वह समुदाय है जिसने प्राकृतिक तौर पर आदिम साम्यवाद देखा है। स्तालिन और माओत्से तुंग ने किसानों से जमीन छिनकर सामूहिक खेती का प्रयोग करते हुए साम्यवाद लाया। मगर, बहुत पीछे नहीं भी जायें तो एक समय ऐसा था जब आदिवासी समाज में सामूहिक खेती का प्रचलन था। कई बुजुर्ग आदिवासियों ने तो सामूहिक रसोई और सामूहिक भोजन भी देखी है। ऐसे में साम्यवाद या मार्क्स के विचारों के प्रति आदिवासियों में आकर्षण स्वाभाविक रहा है। मार्क्सवाद, लेनिनवाद और माओवाद से प्रेरित नक्सलबाड़ी आंदोलन की शुरूआत मई 1967 में पश्चिम बंगाल के जिस सिलीगुड़ी सब डिवीजन इलाके से हुई वहां और आसपास के अधिकतर इलाकों में संथाल, उरांव, मुंडा और राजवंशी आदिवासी समुदायों से लोग थे। नक्सलबाड़ी आंदोलन में आदिवासियों ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया। नक्सलबाड़ी के नायक जंगल संथाल उर्फ धिरेन किस्कू ने कानू सान्याल व चारू मजूमदार के साथ मिलकर कई संघर्ष छेड़े। नक्सलबाड़ी आंदोलन के दौरान जिन गीतों ने युवाओं को जगाया गया, उसमें एक आदिवासी जनगायक सिरिल उरांव के भी कई गीत थे। उनके गीत नक्सलबाड़ी के दौर में आदिवासी जनता गाया करती थी। नक्सलबाड़ी के आंदोलन में आदिवासी महिला सोफिया टोप्पो का भी नाम शामिल है। सोफिया नक्सलबाड़ी की शहीद लड़ाका है। वह एक प्रशिक्षित नर्स थी, जिसने भूमिगत रहकर नक्सलबाड़ी विद्रोह के अनेक घायलों को जीवन दिया था। नक्सलबाड़ी आंदोलन में भूमिका निभाने वाले आदिवासियों में ऐसे सैंकड़ों नाम हैं। किसानों का सशस्त्र विद्रोह तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के तेभागा में भी हुआ। इन दोनों आंदोलनों में भी आदिवासियों ने शिरकत की।

> नक्सलबाड़ी आंदोलन में आदिवासियों ने बढ़चढ़ कर हिस्सा लिया। नक्सलबाड़ी के नायक जंगल संथाल उर्फ धिरेन किस्कू ने कानू सान्याल व चारू मजूमदार के साथ मिलकर कई संघर्ष छेड़े। नक्सलबाड़ी आंदोलन के दौरान जिन गीतों ने युवाओं को जगाया गया, उसमें एक आदिवासी जनगायक सिरिल उरांव के भी कई गीत थे। उनके गीत नक्सलबाड़ी के दौर में आदिवासी जनता गाया करती थी। नक्सलबाड़ी के आंदोलन में आदिवासी महिला सोफिया टोप्पो का भी नाम शामिल है। सोफिया नक्सलबाड़ी की शहीद लड़ाका है। वह एक प्रशिक्षित नर्स थी, जिसने भूमिगत रहकर नक्सलबाड़ी विद्रोह के अनेक घायलों को जीवन दिया था। नक्सलबाड़ी आंदोलन में भूमिका निभाने वाले आदिवासियों में ऐसे सैंकड़ों नाम हैं। किसानों का सशस्त्र विद्रोह तेलंगाना और पश्चिम बंगाल के तेभागा में भी हुआ। इन दोनों आंदोलनों में भी आदिवासियों ने शिरकत की।

बहरहाल, आदिवासीय समाज व्यवस्था का मार्क्सवाद से प्राकृतिक सामंजस्य दिखने के बाद भी आदिवासी और दलितों की समस्याओं को जोड़ कर देखे जाने का दौर शुरू हुआ है। आज अंबेदकर के विचारों से आदिवासियों की समस्याओं के समाधान की राह तलाशी जा रही है। जबकि दलितों और आदिवासियों के सवाल और उनकी समस्याएं अलग-अलग हैं। जेएनयू में वामपंथी छात्र संगठनों के खिलाफ अंबेदकरवादियों ने जिस बापसा (बिरसा-अंबेदकर-फुले स्टूडेंट्स एसोसिएशन) का गठन किया है, उसका नेतृत्व दलितों के ही हाथ है। मगर, बापसा से आदिवासी छात्रों को जोड़ा जा रहा है। तथ्य बताते हैं कि आदिवासियों के सपनों और आंदोलनों का प्रतिनिधित्व अंबेदकरवाद नहीं कर सकता है।

जदयू : नीतीश की नजर में

आरसीपी सिंह बनाम उपेंद्र कुशवाहा

बैठक में सबकी निगाहें नीतीश कुमार, आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा पर टिकी थी। बैठक में उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह ने अपने संबंधों को लेकर सफाई दी। जबकि नीतीश कुमार ने अपने भाषण में उपेंद्र कुशवाहा की तारीफ कर दी। नीतीश कुमार ने कई दफे उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा की। नीतीश कुमार ने उनके काम को सराहा। कुशवाहा के लिए नीतीश की तारीफ इस बात का इशारा कर रही है कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है।

बिहार जदयू पदाधिकारियों की मध्य जुलाई के बाद हुई बैठक में सबकी निगाहें नीतीश कुमार, आरसीपी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा पर टिकी थी। बैठक में उपेंद्र कुशवाहा और आरसीपी सिंह ने अपने संबंधों को लेकर सफाई दी। जबकि नीतीश कुमार ने अपने भाषण में उपेंद्र कुशवाहा की तारीफ कर दी। उधर, केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार आरसीपी सिंह और नीतीश कुमार पार्टी के कार्यक्रम में एक साथ मौजूद थे। हालांकि दोनों वर्चुअली जुड़े थे। सीएम आवास से नीतीश कुमार तो दिल्ली पार्टी ऑफिस से आरसीपी सिंह शामिल हुए।

रोलोसपा से जदयू में आने के बाद पहली बार ही उपेंद्र कुशवाहा पार्टी के किसी कार्यक्रम में मौजूद थे। बैठक में बिहार के तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे। पटना ऑफिस में आयोजित बैठक में प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, वशिष्ठ नारायण सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, विजय चौधरी, अशोक चौधरी समेत पार्टी के पदाधिकारी और नेता मौजूद रहे। इसी दौरान जदयू संसदीय बोर्ड के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आरसीपी सिंह से अपने संबंधों पर सफाई दी। उन्होंने किसी भी तरह के विवाद को खारिज किया। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि हमारे नेता और कार्यकर्ता किसी कंफ्यूजन में न रहें। हम दोनों (आरसीपी-उपेंद्र) में कोई मतभेद नहीं है। अबतक कई दफे राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात हुई है। उनके साथ बैठ कर चाय पीए हैं तो फिर मतभेद या मनभेद की बात कहां है?

दूसरी ओर मीडिया के अटकलों पर भी उपेंद्र कुशवाहा ने बयान दिया। उन्होंने कहा कि मीडिया में यह खबर चलती है कि आरसीपी सिंह से हमारा संबंध ठीक नहीं है, जिसकी वजह से कुछ कार्यकर्ता कंफ्यूज कर जाते हैं। ऐसे में सबको सतर्क रहने की जरूरत है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा ने इतना जरूर कहा कि संगठन में सुस्ती है।

मोहित कुमार

चूंकि संगठन का काम फिलहाल आरसीपी सिंह देख रहे हैं। कुशवाहा ने कहा कि हमें जेडीयू को नंबर- वन पार्टी बनाना है। संगठन में कुछ सुस्ती जरूर है, जिसे दूर कर लिया जाएगा। उपेंद्र कुशवाहा ने नीतीश कुमार की भी जमकर तारीफ की। उपेंद्र कुशवाहा के बाद बारी थी राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह की। उन्होंने कहा कि आज बहुत अच्छा लगा कि खुद उपेंद्र कुशवाहा ने बड़ी साफगोई से सारी बातें सामने रख दी। अब सबकुछ साफ हो गया है। आरसीपी सिंह ने कहा कि वे भले ही केंद्रीय बन गए हैं लेकिन संगठन के काम में कोई कमी नहीं आएगी। शनिवार और रविवार को वो संगठन के कामकाज को देखेंगे। बैठक के बाद दिल्ली में आरसीपी सिंह से मीडिया ने उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहने को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी मिलती है, उसे वो बखूबी निभाते हैं।

जदयू का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने से पहले वो राज्यसभा में सदन के नेता थे। लेकिन, जैसे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, पार्टी ने राज्यसभा में रामनाथ ठाकुर को नेता बनाया। फिलहाल वे केंद्र में मंत्री बने हैं, आगे पार्टी जो तय करेगी वो स्वीकार करेंगे। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी प्रदेश पदाधिकारियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हमने ही उपेंद्र कुशवाहा को जिलों का भ्रमण करने को कहा था। हमने कहा था कि ग्राउंड लेवल पर जाकर देखिए क्या कुछ हो रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने दूसरे नेताओं को भी इनसे सीख लेकर दौरा की सलाह दी। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि ऐसा नहीं कि सामानंतर ही भ्रमण करने लगें। बैठक के दौरान नीतीश कुमार ने कई दफे उपेंद्र कुशवाहा की चर्चा की। नीतीश कुमार ने उनके काम को सराहा। कुशवाहा के लिए नीतीश की तारीफ इस बात का इशारा कर रही है कि उन्हें बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने कार्यकाल में किए गए कामों के बारे में पार्टी पदाधिकारियों को विस्तार से बताया।'सोशल मीडिया पर पार्टी को और ज्यादा ऐक्टिव रहने की जरुरत' भी बतायी गयी। नीतीश कुमार अपने भाषण में सोशल मीडिया को लेकर काफी अलर्ट दिखे। उन्होंने कहा कि आज सोशल मीडिया पर तरह-तरह की बातें लिखी जाती है। ऐसे में पार्टी के नेता उसका जवाब दें। दरअसल, राजद नेता तेजस्वी यादव सोशल मीडिया के जरिए नीतीश कुमार पर काफी अटैकिंग मोड में हैं। नीतीश कुमार को लगता है कि उनकी पार्टी की तरफ से उसका काउंटर ठीक तरीके से नहीं किया जा रहा है।

15 अगस्त को आजाद हुआ पाकिस्तान

14 को क्यों मनाता है स्वतंत्रता दिवस?

को सत्ता का हस्तांतरण अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को करना था जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के एकमात्र प्रतिनिधि थे। लेकिन, माउंटबेटन एक ही वक्त पर नई दिल्ली और कराची में मौजूद नहीं हो सकते थे। न ही ऐसा हो सकता था कि वे 15 अगस्त को पहले भारत को सत्ता का हस्तांतरण करें और फिर कराची जाएं, क्योंकि भारत को सत्ता हस्तातंरित करते ही कानून के मुताबिक उनकी भूमिका भारत के गवर्नर जनरल की हो जानी थी। इसलिए व्यावहारिक रास्ता यही था कि वे वायसराय रहते हुए 14 अगस्त को ही पाकिस्तान को सत्ता हस्तांतरित कर दें और भारत के लिए यह काम अगले दिन हो।

विकास शर्मा

जाने-माने पाकिस्तानी इतिहासकार केके अजीज'मर्डर ऑफ हिस्ट्री' नामक अपनी किताब में लिखते हैं,'आम धारणा यही है और आजादी के आधिकारिक समारोहों ने इसे मजबूत ही किया है कि पाकिस्तान 14 अगस्त को आजाद हुआ। लेकिन, सच यह नहीं है। जो इंडियन इंडिपेंडेंस बिल चार जुलाई को ब्रिटिश संसद में पेश हुआ था और जिसने 15 जुलाई को कानून की शक्ल ली थी, उसमें कहा गया था कि 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को भारत का बंटवारा होगा। जिससे भारत और पाकिस्तान नामक दो नये देश अस्तित्व में आ जाएंगे। इन दो नये देशों को सत्ता का हस्तांतरण अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को करना था जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के एकमात्र प्रतिनिधि थे। लेकिन, माउंटबेटन एक ही वक्त पर नई दिल्ली और कराची में मौजूद नहीं हो सकते थे। न ही ऐसा हो सकता था कि वे 15 अगस्त को पहले भारत को सत्ता का हस्तांतरण करें और फिर कराची जाएं, क्योंकि भारत को सत्ता हस्तातंरित करते ही कानून के मुताबिक उनकी भूमिका भारत के गवर्नर जनरल की हो जानी थी। इसलिए व्यावहारिक रास्ता यही था कि वे वायसराय रहते हुए 14 अगस्त को ही पाकिस्तान को सत्ता हस्तांतरित कर दें और भारत के लिए यह काम अगले दिन हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पाकिस्तान को अपनी आजादी 14 अगस्त को मिली क्योंकि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में यह तारीख 15 अगस्त ही थी।''

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी मुहम्मद अली ने भी अपनी किताब'द इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान' में इस बात की पुष्टि की है। उनके मुताबिक 15 अगस्त 1947 को रमजान का आखिरी जुमा था जो इस्लामी मान्यताओं के हिसाब से सबसे मुबारक दिनों में से एक है। मुहम्मद अली लिखते हैं कि इस मुबारक दिन पर कायदे आजम पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने, कैबिनेट ने शपथ ली, चांद सितारे वाला झंडा फहराया गया और दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान वजूद में आया। कायदे आजम मुहम्मद अली जिन्ना ने खुद 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस की शुरूआत करते हुए देश के नाम यह संदेश जारी किया था,'ढेर सारी खुशियों के साथ मैं आपको बधाइयां देता हूं। 15 अगस्त स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र पाकिस्तान का जन्मदिन है।' 1948 में पाकिस्तान ने जो पहला डाक टिकट जारी किया उसमें आजादी की तारीख 15 अगस्त 1947 ही दर्ज है।

लेकिन, आज रेडियो पाकिस्तान 15 अगस्त की बधाई वाला जिन्ना का संदेश 14 अगस्त को प्रसारित करता है।

दरअसल, 1948 में जश्ने आजादी की इस तारीख को 14 अगस्त कर दिया गया था। ऐसा क्यों हुआ इसकी पड़ताल करने पर अलग-अलग बातें सामने आती हैं। कई रिपोर्टों में कहा गया है कि उस साल 14 अगस्त को रमजान का 27वां दिन यानी शब-ए-कद्र पड़ रहा था। मान्यता है कि इसी रात धार्मिक ग्रंथ कुरआन मुकम्मल हुआ था। इसके बाद पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को ही मनाया जाने लगा। यह भी कहा जाता है कि 14 अगस्त को वायसराय के सत्ता हस्तांतरित करने के बाद ही कराची में पाकिस्तानी झंडा फहरा दिया गया था और इसलिए बाद में पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस की तारीख 14 अगस्त ही कर दी गयी। हालांकि भारत और पाकिस्तान में एक वर्ग है जिसका मानना है कि पाकिस्तान ने अपने स्वतंत्रता दिवस की तारीख 14 अगस्त इसलिए की कि उसे भारत से अलग दिखना था। कुछ तो इसके तार राष्ट्रवाद से जोड़ते हुए यह भी कहते हैं कि पाकिस्तान के कर्ता-धर्ता यह दिखाना चाहते थे कि उनका देश भारत से एक दिन पहले आजाद हुआ है। पाकिस्तानी अखबार डॉन में इस बारे में छपी एक खबर पर टिप्पणी करते हुए सना नाम की एक पाठिका कहती हैं कि''इससे क्या फर्क पड़ता है कि हम कौन से दिन आजाद हुए। अहम बात यह है कि आजादी के बाद से अब तक हमने क्या हासिल किया है।''

राखी के जरिये एकजुट हुए हिंदू-मुसलमान

माध्यम बने रवींद्रनाथ टैगोर

बंगाल के बंटवारे का पूरे देश में भारी विरोध होने लगा। पूरे देश में विदेशी कपड़ों की होली जलाना आम बात हो गई। लेकिन, बाकी मामलों की तरह बंगाल में इस विरोध ने एक अलग और अनोखा रास्ता अख्तियार किया। इस रास्ते के प्रणेता थे रवींद्रनाथ टैगोर। टैगोर ने ऐलान किया कि बंटवारे के दिन यानी 16 अक्टूबर को राष्ट्रीय शोक दिवस होगा। साथ ही बंगालियों के घर में उस दिन खाना नहीं बनेगा। बंगाल के हिंदुओं और मुसलमानों के आपसी भाईचारे का संदेश देने के लिए टैगोर ने राखी का उपयोग किया। रवींद्रनाथ टैगोर चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को राखी बांधें और शपथ लें कि वे जीवनभर एक-दूसरे की सुरक्षा का एक ऐसा रिश्ता बनाए रखेंगे जिसे कोई तोड़ न सके।

जाने-माने पाकिस्तानी इतिहासकार केके अजीज 'मर्डर ऑफ हिस्ट्री' नामक अपनी किताब में लिखते हैं,'आम धारणा यही है और आजादी के आधिकारिक समारोहों ने इसे मजबूत ही किया है कि पाकिस्तान 14 अगस्त को आजाद हुआ। लेकिन, सच यह नहीं है। जो इंडियन इंडिपेंडेंस बिल चार जुलाई को ब्रिटिश संसद में पेश हुआ था और जिसने 15 जुलाई को कानून की शक्ल ली थी, उसमें कहा गया था कि 14-15 अगस्त की मध्यरात्रि को भारत का बंटवारा होगा। जिससे भारत और पाकिस्तान नामक दो नये देश अस्तित्व में आ जाएंगे। इन दो नये देशों को सत्ता का हस्तांतरण अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन को करना था जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के एकमात्र प्रतिनिधि थे। लेकिन, माउंटबेटन एक ही वक्त पर नई दिल्ली और कराची में मौजूद नहीं हो सकते थे। न ही ऐसा हो सकता था कि वे 15 अगस्त को पहले भारत को सत्ता का हस्तांतरण करें और फिर कराची जाएं, क्योंकि भारत को सत्ता हस्तांतरित करते ही कानून के मुताबिक उनकी भूमिका भारत के गवर्नर जनरल की हो जानी थी। इसलिए व्यावहारिक रास्ता यही था कि वे वायसराय रहते हुए 14 अगस्त को ही पाकिस्तान को सत्ता हस्तांतरित कर दें और भारत के लिए यह काम अगले दिन हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि पाकिस्तान को अपनी आजादी 14 अगस्त को मिली क्योंकि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में यह तारीख 15 अगस्त ही थी।''

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी मुहम्मद अली ने भी अपनी किताब'द इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान' में इस बात की पुष्टि की है। उनके मुताबिक 15 अगस्त 1947 को रमजान का आखिरी जुमा था जो इस्लामी मान्यताओं के हिसाब से सबसे मुबारक दिनों में से एक है। मुहम्मद अली लिखते हैं कि इस मुबारक दिन पर कायदे आजम पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बने, कैबिनेट ने शपथ ली, चांद सितारे वाला झंडा फहराया गया और दुनिया के नक्शे पर पाकिस्तान वजूद में आया। कायदे आजम मुहम्मद अली जिन्ना ने खुद 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग सर्विस की शुरूआत करते हुए देश के नाम यह संदेश जारी किया था,'ढेर सारी खुशियों के साथ मैं आपको बधाइयां देता हूं। 15 अगस्त स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र पाकिस्तान का जन्मदिन है।' 1948 में पाकिस्तान ने जो पहला डाक टिकट जारी किया उसमें आजादी की तारीख 15 अगस्त 1947 ही दर्ज है।

लेकिन, आज रेडियो पाकिस्तान 15 अगस्त की बधाई वाला जिन्ना का संदेश 14 अगस्त को प्रसारित करता है।

दरअसल, 1948 में जश्ने आजादी की इस तारीख को 14 अगस्त कर दिया गया था। ऐसा क्यों हुआ इसकी पड़ताल करने पर अलग-अलग बातें सामने आती हैं। कई रिपोर्टों में कहा गया है कि उस साल 14 अगस्त को रमजान का 27वां दिन यानी शब-ए-कद्र पड़ रहा था। मान्यता है कि इसी रात धार्मिक ग्रंथ कुरआन मुकम्मल हुआ था। इसके बाद पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को ही मनाया जाने लगा। यह भी कहा जाता है कि 14 अगस्त को वायसराय के सत्ता हस्तांतरित करने के बाद ही कराची में पाकिस्तानी झंडा फहरा दिया गया था और इसलिए बाद में पाकिस्तान के स्वतंत्रता दिवस की तारीख 14 अगस्त ही कर दी गयी। हालांकि भारत और पाकिस्तान में एक वर्ग है जिसका मानना है कि पाकिस्तान ने अपने स्वतंत्रता दिवस की तारीख 14 अगस्त इसलिए की कि उसे भारत से अलग दिखना था। कुछ तो इसके तार राष्ट्रवाद से जोड़ते हुए यह भी कहते हैं कि पाकिस्तान के कर्ता-धर्ता यह दिखाना चाहते थे कि उनका देश भारत से एक दिन पहले आजाद हुआ है। पाकिस्तानी अखबार डॉन में इस बारे में छपी एक खबर पर टिप्पणी करते हुए सना नाम की एक पाठिका कहती हैं कि'इससे क्या फर्क पड़ता है कि हम कौन से दिन आजाद हुए। अहम बात यह है कि आजादी के बाद से अब तक हमने क्या हासिल किया है।''

सुतापा साहा

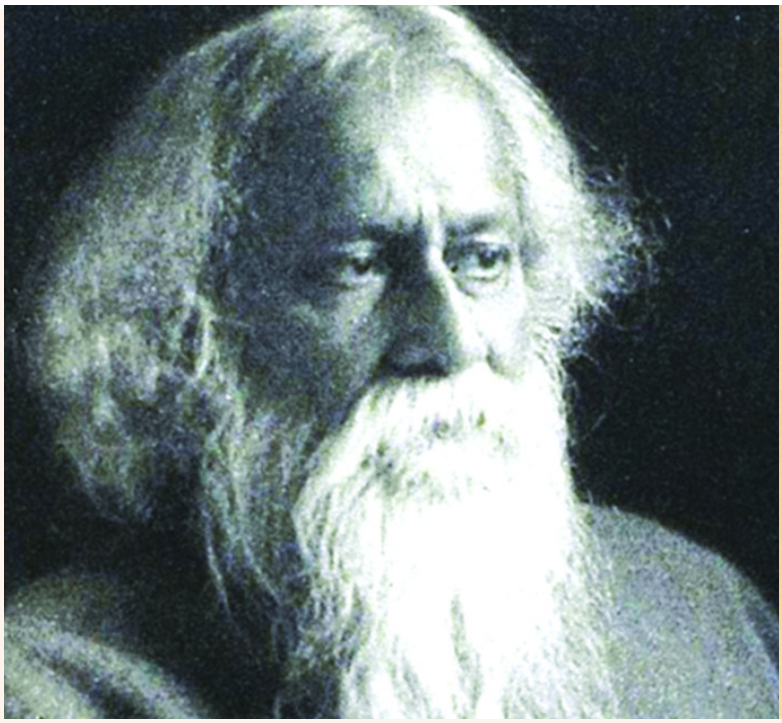

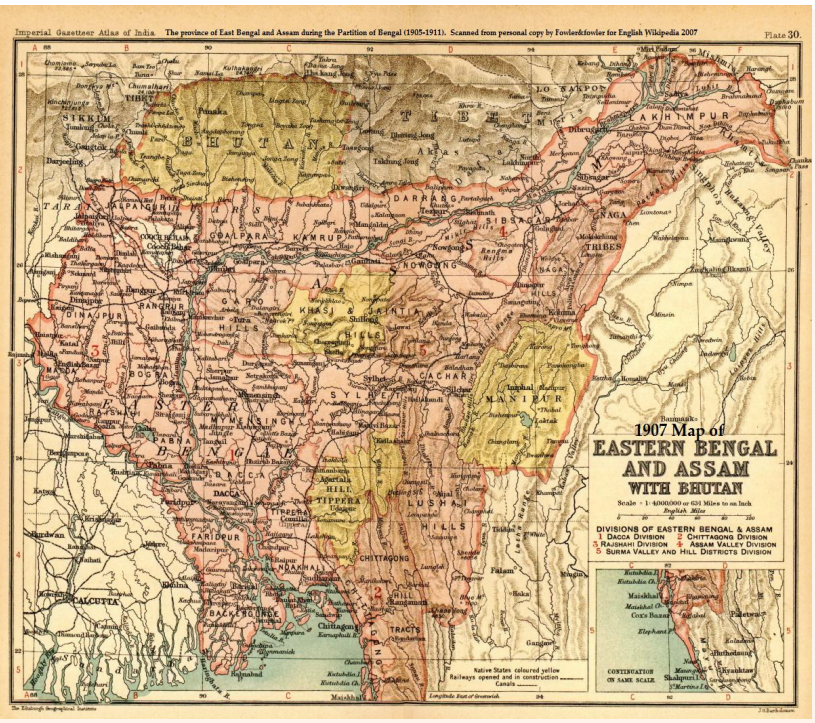

पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता की अपनी चाल है। यह किसी बनी-बनायी लकीर पर नहीं चलती। नवरात्रि पर बाकी देश उपवास करता है। जबकि कोलकाता में लोगों के लिए दुर्गा पूजा का मतलब होता है भव्य भोजन। पूरे देश में दशहरा उल्लास से मनाया जाता है। कोलकाता में बिजया को लोगों की आंखें नम होती हैं। दीवाली के दिन बाकी भारत में लक्ष्मी पूजा होती है तो कोलकाता में काली पूजा। इसलिए यह हैरानी की बात नहीं कि रक्षा बंधन के मामले में भी यहां का एक अलग किस्सा है।

वर्ष 1905 में यह किस्सा शुरू हुआ था। उन दिनों ब्रिटिश भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल लार्ज कर्जन ने बंगाल के विभाजन का ऐलान किया। तब के बंगाल में आज का पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम और वह इलाका भी शामिल था जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं। क्षेत्रफल में यह फ्रांस जितना बड़ा था, लेकिन इसकी आबादी कई गुना ज्यादा थी। इतने बड़े सूबे खासकर इसके पूर्वी हिस्से का प्रशासन संभालना ब्रिटिश सरकार के लिए मुश्किल साबित हो रहा था इसलिए सरकार ने इसके दो टुकड़े करने का ऐलान कर दिया। योजना के तहत असम के साथ ढाका, त्रिपुरा, नोआखाली, चटगांव और मालदा जैसे इलाकों को मिलाकर पूर्वी बंगाल और असम नाम का एक नया राज्य बनना था। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि ऐसा उसे मजबूरी में करना पड़ रहा है और इससे प्रशासनिक कामकाज बेहतर होगा। लेकिन, बंगाली समुदाय को इसमें छिपी साजिश की गंध आ गई। बंगाल का पूर्वी हिस्सा मुस्लिम बहुल था जबकि पश्चिमी हिस्से में हिंदू समुदाय की आबादी ज्यादा थी। जल्द ही लोगों में चर्चा होने लगी कि यह अंग्रेजों की बांटो और राज करो वाली पुरानी चाल है।

बंगाल के बंटवारे का पूरे देश में भारी विरोध होने लगा। कांग्रेस ने इसके विरोध में स्वदेशी अभियान की घोषणा की। इसके तहत सारे विदेशी सामानों का बहिष्कार किया जाना था। यानी ब्रिटिश सरकार पर वहां चोट करने की तैयारी हुई जहां इसे सबसे ज्यादा दर्द हो। पूरे देश में विदेशी कपड़ों की होली जलाना आम बात हो गई। लेकिन, बाकी मामलों की तरह बंगाल में इस विरोध ने एक अलग और अनोखा रास्ता अख्तियार किया। इस रास्ते के प्रणेता थे रवींद्रनाथ टैगोर। टैगोर ने ऐलान किया कि बंटवारे के दिन यानी 16 अक्टूबर को राष्ट्रीय शोक दिवस होगा। साथ ही बंगालियों के घर में उस दिन खाना नहीं बनेगा। बंगाल के हिंदुओं और मुसलमानों के आपसी भाईचारे का संदेश देने के लिए टैगोर ने राखी का उपयोग किया। रवींद्रनाथ टैगोर चाहते थे कि हिंदू और मुसलमान एक दूसरे को राखी बांधें और शपथ लें कि वे जीवनभर एक-दूसरे की सुरक्षा का एक ऐसा रिश्ता बनाए रखेंगे जिसे कोई तोड़ न सके।

16 अक्टूबर को टैगोर ने गंगा में डुबकी के साथ अपना दिन शुरू किया। गंगा किनारे से उनकी अगुवाई में एक जुलूस शुरू हुआ। टैगोर कोलकाता की सड़कों पर चलते जा रहे थे और जो भी मिल रहा था उसे राखी बांध रहे थे। यह उत्साही कवि अपने साथ राखियों का अंबार लेकर निकला था। हालांकि जब उन्होंने अपने घर के पास बनी एक मस्जिद में जाकर अंदर मौजूद मौलवियों को राखी बांधने की बात कही तो लोगों को लगा कि वे उत्साह के अतिरेक में चीजों को बहुत आगे ले जा रहे हैं। लेकिन, टैगोर पीछे हटने वाले नहीं थे। मौलवियों को भी इस पर कोई ऐतराज नहीं था। इस तरह जुलूस आगे बढ़ता गया।

टैगोर जहां-जहां से गुजरे, सड़क की दोनों तरफ लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। उनके साथ चल रहे लोग खासकर इस मौके के लिए लिखा गया उनका गीत गा रहे थे। इस गीत में ईश्वर से बंगाल को सुरक्षित और एकजुट रखने की प्रार्थना की गई थी। छतों पर खड़ी महिलाएं जुलूस पर चावल फेंक रही थीं और शंख बजा रही थीं। इस विरोध अभियान का असर हुआ। कुछ समय के लिए बंगाल विभाजित होने से बच गया। हालांकि अंग्रेजों के लिए बंगाल को संभालना मुश्किल हो रहा था इसलिए 1912 में बिहार, असम और उड़ीसा को इससे अलग कर दिया गया। इस बार यह बंटवारा भाषाई आधार पर हुआ था। इसके 35 साल बाद सीधी कार्रवाई के तहत जो खून खराबा हुआ उसने एकजुट बंगाल के सपने का आखिरकार अंत कर दिया।

“

वर्ष 1905 में यह किस्सा शुरू हुआ था। उन दिनों ब्रिटिश भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल लार्ज कर्जन ने बंगाल के विभाजन का ऐलान किया। तब के बंगाल में आज का पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम और वह इलाका भी शामिल था जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं। क्षेत्रफल में यह फ्रांस जितना बड़ा था, लेकिन इसकी आबादी कई गुना ज्यादा थी। इतने बड़े सूबे खासकर इसके पूर्वी हिस्से का प्रशासन संभालना ब्रिटिश सरकार के लिए मुश्किल साबित हो रहा था इसलिए सरकार ने इसके दो टुकड़े करने का ऐलान कर दिया। योजना के तहत असम के साथ ढाका, त्रिपुरा, नोआखाली, चटगांव और मालदा जैसे इलाकों को मिलाकर पूर्वी बंगाल और असम नाम का एक नया राज्य बनना था। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि ऐसा उसे मजबूरी में करना पड़ रहा है और इससे प्रशासनिक कामकाज बेहतर होगा। लेकिन, बंगाली समुदाय को इसमें छिपी साजिश की गंध आ गई। बंगाल का पूर्वी हिस्सा मुस्लिम बहुल था जबकि पश्चिमी हिस्से में हिंदू समुदाय की आबादी ज्यादा थी। जल्द ही लोगों में चर्चा होने लगी कि यह अंग्रेजों की बांटो और राज करो वाली पुरानी चाल है।

उच्च सदन में छिछालेदर संसद की गरिमा आहत

सदन में आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव पेगासस मामले पर बोलने के लिए खड़े हुए तो तृणमूल सांसद शांतनु सेन ने उनके हाथ से पेपर छीनकर फाड़ दिया। इतना ही नहीं पेपर के टुकड़े उपसभापति की कुर्सी की तरफ फेंक दिए। इसके बाद मार्शल को बीच-बचाव के लिए आना पड़ा। पेगासस मामले में जब आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव पेगसस मामले पर स्टेटमेंट देने के लिए खड़े हुए वैसे ही विपक्षी सांसद सदन के वेल में पहुंचे गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सो, उपसभापति हरिवंश ने विरोधी सांसदों से असंसदीय व्यवहार ना करने और अपनी सीटों पर वापस जाने का आग्रह किया।

तृणमूल सांसद शांतनु सेन का विवादों से नाता कोई नया नहीं है। हाल ही में कोलकाता में एक फर्जी कोविड वैक्सीन कैंप को लेकर बहुत बड़ा विवाद हुआ था। उसमें घोटाले के मास्टरमाइंड के साथ इनकी एक तस्वीर खूब वायरल हुई थी। आरोपी देबांजन देब जो कि फर्जी आईएएस बनकर यह धोखाधड़ी कर रहा था, उसने अपने ट्विटर हैंडल पर ये तस्वीर अपलोड की थी। लेकिन, बाद में डॉक्टर सेन ने फर्जी वैक्सीन के आरोपी से अपने रिश्तों का खंडन किया था।

आरके सिंह

पेगासस को लेकर हंगामे के दौरान उच्च सदन यानी राज्यसभा की गरिमा आहत हुई और संसद की मयार्दा को भी नुकसान पहुंचा है। राज्यसभा में तब हाई ड्रामा देखने को मिला जब विपक्ष ने कई मुद्दों पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। तृणमूल कांग्रेस सांसदों ने सदन में उस समय भारी हंगामा किया जब आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव पेगासस मामले पर स्टेटमेंट देने के लिए खड़े हुए थे। तृणमूल सांसद शांतनु सेन ने आईटी मंत्री के हाथ से स्टेटमेंट पेपर छीनकर फाड़ दिया। इतना ही नहीं पेपर के टुकड़े उपसभापति की कुर्सी की तरफ फेंक दिए। इसके बाद मार्शल को बीच-बचाव के लिए आना पड़ा। पेगासस मामले में जब आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव पेगसस मामले पर स्टेटमेंट देने के लिए खड़े हुए वैसे ही विपक्षी सांसद सदन के वेल में पहुंचे गए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। सो, उपसभापति हरिवंश ने विरोधी सांसदों से असंसदीय व्यवहार ना करने और अपनी सीटों पर वापस जाने व मंत्री को अपना बयान पूरा करने का आग्रह किया।

हंगामा जारी रहने के कारण उपसभापति ने सदन की कार्यवाही तत्काल स्थगित कर दी। हंगामे के बाद राज्यसभा अगले दिन तक के लिए स्थगित की गयी। दरअसल, विपक्षी सांसदों द्वारा पेगासस स्पाइवेयर और अन्य का उपयोग करके कथित जासूसी का मुद्दा उठाए जाने के बाद सदन को दो बार स्थगित किया गया था। उधर पेगासस मामले पर राज्यसभा में बात रखते हुए आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने मीडिया रिपोर्ट पर सवाल उठाए, उन्होंने कहा कि संसद सत्र से एक दिन पहले पेगसस मामले पर प्रेस रिपोर्ट आना सिर्फ संयोग नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि पेगसस से व्हाट्सएप की हेकिंग का दावा पहले भी किया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सभी ने इस बात को नकारा था।

मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा में सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ जिस तरह से टीएमसी सांसदों ने बदसलूकी की उसे लेकर भाजपा मुखर है। भाजपा ने टीएमसी सांसद के इस व्यवहार की कड़ी निंदा की। साथ ही भाजपा ने राज्यसभा अध्यक्ष से आईटी मंत्री से दुर्व्यवहार के लिए टीएमसी सांसद शांतनु सेन के निलंबन का अनुरोध किया। उल्लेखनीय है कि फ्रांस की संस्था फॉरबिडेन स्टोरीज और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने मिलकर खुलासा किया है कि इजरायली कंपनी एनएसओ के स्पाईवेयर पेगासस के जरिए दुनिया भर की सरकारें पत्रकारों, कानूनविदों, नेताओं और नेताओं के रिश्तेदारों की जासूसी करा रही हैं।

इस जांच को पेगासस प्रोजेक्ट नाम दिया गया है। निगरानी वाली लिस्ट में 50 हजार लोगों के नाम हैं, जो पहली लिस्ट पत्रकारों की निकली हैं उसमें 40 भारतीय नाम हैं। मीडिया में इस खबर के आने के बाद से ही विवाद शुरू हो गया है। इस पूरी खबर के बाद विपक्ष मोदी सरकार पर हावी हो गया है। हालांकि भारत सरकार ने किसी भी प्रकार की जारूसी से इंकार किया है।

बहरहाल, तृणमूल सांसद शांतनु सेन ने आरोप लगाया है कि हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उन्हें धमकी दी और गाली-गलौज की है। शांतनु सेन ने आरोप लगाया कि मंत्री उन पर शारीरिक हमला करने वाले थे, हालांकि उन्हें उनके सहयोगियों ने बचा लिया। शांतनु सेन ने कहा कि सदन स्थगित होने के बाद, मुझे अचानक हरदीप पुरी ने बहुत खराब तरीके से बुलाया। मैं फिर भी उनके पास गया लेकिन उन्होंने मुझे धमकी देना शुरू कर दिया। वह मुझे गालियां दे रहे थे और मुझे शारीरिक रूप से हमला करने वाले थे। मेरा लगभग घेराव किया गया था। शांतनु सेन ने बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भगवान का शुक्र है, मेरे सहयोगियों ने इसे देखा और मुझे बचाया। यह बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। उधर, आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के हाथों से संसद के सदन में पेपर छीनकर फाड़ने को लेकर टीएमसी सांसद शांतनु सेन पर कार्यवाही हुई। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने सदन में मंत्री के बयान देते समय उनके व्यवहार पर बहुत ही दुख जताया। शांतनु सेन से कहा गया कि कृप्या सदन से जाइए और सदन की कार्यवाही चलने दीजिए। उन्हें पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि''सदन में हो रही घटनाओं पर मैं बहुत ही ज्यादा आहत हूं। दुर्भाग्य से, मंत्री से सदन की कार्यवाही से जुड़े पेपर छीनकर और उसे टुकड़ों में फाड़ने से सदन की कार्यवाही नीचले स्तर पर पहुंच गई है। इस तरह का व्यवहार निश्चित तौर पर संसदीय लोकतंत्र पर हमला है।''

मानसून सत्र के दौरान जिस तरह से आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के भाषण के दौरान टीएमसी सांसद शांतनु मिश्रा ने मंत्री के बयान के कागज को उनसे छीनकर फेंक दिया उसके बाद इस मामले को लेकर आरोप-प्रत्यारोप शुरू हो गया है। अश्विनी वैष्णव ने टीएमसी पर हमला बोलते हुए कहा कि टीएमसी अब संसद में हिंसा की संस्कृति को लेकर आ रही है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि टीमसी की संस्कृति हिंसा की है बंगाल में और अब ये लोग इसी संस्कृति को संसद में भी लाने की कोशिश कर रहे हैं। आखिर ये लोग आने वाली पीढ़ियों के सांसद को क्या संदेश देना चाहते हैं।

पेशे से डॉक्टर टीएमसी सांसद ने अपने ट्विटर हैंडल पर जो प्रोफाइल फोटो लगाई है, उसमें उन्होंने एक बहुत ही अच्छी बात लिखी है-'आई कांट स्टे ऐट होम...आई एम हेल्थकेयर वर्कर'। लेकिन, अगर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने उन्हें राज्यसभा में भी भेजा है, तो भी जनता के परोक्ष प्रतिनिधि होने के नाते उनका कुछ फर्ज बनता है, जो कि सदन में उनके आचरण में नहीं दिखा। डॉक्टर शांतनु सेन ने सदन की कार्यवाही के दौरान पेगासस विवाद पर बयान दे रहे आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के हाथ से उनके बयान वाला पेपर छीनकर फाड़ दिया था। उनकी इसी हरकत के चलते शुक्रवार को उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई हुई है और उन्हें मौजूदा सत्र के लिए सदन से निर्लंबित कर दिया गया है। संसदीय कार्य राज्यमंत्री वी मुरलीधरन ने उनके निलंबन का प्रस्ताव पेश किया, जिसे ध्वनि मत से पारित कर दिया गया। इधर शांतनु सेन का आरोप है कि सदन के अंदर केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने उन्हें धमकाया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया और उनपर शारीरिक हमला करने ही वाले थे। उन्होंने ट्वीट कर-के तंज भरे अंदाज में लिखा है,''धन्यवाद नरेंद्र मोदीजी, क्योंकि उनके मंत्री हरदीप सिंह ने मुझे संसद के सदन के भीतर धमकाया, दुर्व्यवहार किया और मुझ पर शारीरिक हमला करने ही वाले थे। जानता था कि सदन हमेशा विपक्ष के लिए होता है। अब ममता बनर्जी के सांसद को भाजपा के मंत्रियों की गुंडागर्दी का सामना करना पड़ रहा है।'' पेशे से डॉक्टर रहे शांतनु सेन ने एक और ट्वीट करके मोदी सरकार पर हमला किया है। उन्होंने लिखा है,''भारतीय बिल्कुल ही सुरक्षित नहीं हैं। ऑक्सीजन की किल्लत से मर सकते हैं। वैक्सीन की कमी के चलते भी मर सकते हैं और मरने के बाद उनका शव गंगा में तैर सकता है। पेगासस निजता छीन लेता है। संसद में लोकतांत्रिक तरीके से चर्चा नहीं होती। अब एक मंत्री, सांसद को सदन के भीतर धमकाता है।''

-फर्जी कोविड वैक्सीन कैंप और शांतनु

जो हो, डॉ शांतनु सेन का विवादों से नाता कोई नया नहीं है। हाल ही में कोलकाता में एक फर्जी कोविड वैक्सीन कैंप को लेकर बहुत बड़ा विवाद हुआ था। उसमें घोटाले के मास्टरमाइंड के साथ इनकी एक तस्वीर खूब वायरल हुई थी। आरोपी देबांजन देब जो कि फर्जी आईएएस बनकर यह धोखाधड़ी कर रहा था, उसने अपने ट्विटर हैंडल पर ये तस्वीर अपलोड की थी। लेकिन, बाद में डॉक्टर सेन ने फर्जी वैक्सीन के आरोपी से अपने रिश्तों का खंडन किया था। उन्होंने कहा था कि कोरोना की पहली लहर के दौरान आरोपी सोशल वर्कर के तौर पर मुझे मिलने आया होगा, न कि आईएएस ऑफिसर बनकर और यह तभी की तस्वीर होगी। बता दें कि इसी तस्वीर को लेकर भाजपा ममता सरकार पर हमलावर थी और फर्जी वैक्सीन कैंप मामले की जांच सेंट्रल एजेंसी से करवाने की मांग कर रही थी। बता दें कि इस फर्जी वैक्सीनेशन कैंप की शिकार टीएमसी की सांसद मिमी चक्रबर्ती भी बन गई थीं। शांतनु सेन पहले इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के नेशनल प्रेसिडेंट थे और अभी इसके स्टेट सेक्रेटरी हैं। आईएमए अध्यक्ष के तौर पर उनका कार्यकाल 2018 से 2019 के बीच रहा। वे कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के काउंसिलर भी रह चुके हैं। मूल रूप से ये पश्चिम बंगाल के मुर्शीदाबाद इलाके के रहने वाले हैं।

तृणमूल सांसद शांतनु सेन ने आरोप लगाया है कि हंगामे के बीच सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद राज्यसभा में केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने उन्हें धमकी दी और गाली-गलौज की है। शांतनु सेन ने आरोप लगाया कि मंत्री उन पर शारीरिक हमला करने वाले थे, हालांकि उन्हें उनके सहयोगियों ने बचा लिया। शांतनु सेन ने कहा कि सदन स्थगित होने के बाद, मुझे अचानक हरदीप पुरी ने बहुत खराब तरीके से बुलाया। मैं फिर भी उनके पास गया लेकिन उन्होंने मुझे धमकी देना शुरू कर दिया। वह मुझे गालियां दे रहे थे और मुझे शारीरिक रूप से हमला करने वाले थे। मेरा लगभग घेराव किया गया था। शांतनु सेन ने बाद में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि भगवान का शुक्र है, मेरे सहयोगियों ने इसे देखा और मुझे बचाया। यह बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है।

जन्मदिन

मीना कुमारी पर फिल्माए गए एक अमर गीत में वे होकर भी नहीं थीं!

रवि सिंह

पाकीजा में किए गए अभिनय को मीना कुमार के श्रेष्ठतम कामों में ऐसे ही नहीं गिना जाता. सिवाय एक गीत के जिसमें वे होकर भी नहीं थीं!

फिल्म'पाकीजा' को बनने में पूरे 14 साल लगे थे। 1972 में तैयार हुई थी यह मूवी। कमाल अमरोही की ख्वाबो-खयाली थी कि जिस तरह शाहजहां ने अपनी पत्नी के लिए ताजमहल बनवाया, अमरोही ने भी अपनी पत्नी मीना कुमारी के लिए'पाकीजा' बनायी। लिहाजा,'पाकीजा' ने भी ताजमहल सरीखी प्रसिद्धी हासिल की और मीना कुमारी की मौत की वजह से इस फिल्म को देखने के लिए दर्शक टिकट खिड़कियों पर टूट पड़े।

लंबी बीमारी के बाद दम तोड़ने वाली मीना कुमारी की यह आखिरी फिल्म कहलाई और इसी फिल्म के लिए उन्होंने अपने जीवन का आखिरी फिल्म प्रीमियर भी अटेंड किया। कहते हैं कि यहीं पर,'पाकीजा' देखने के बाद किसी मशहूर हस्ती ने उनसे कहा था,'शाहकार बन गया!' इस कलात्मक फिल्म के बनने के दौरान कई बार फिल्मांकन बाधित हुआ। कमाल अमरोही और मीना कुमारी अलग हो गए और तीखी तकरार के बाद जब वापस काम शुरू हुआ तब मीना गंभीर बीमारी की चपेट में आ गयीं। शूटिंग रुक-रुककर होने लगी और शारीरिक थकान देने वाले कई गीतों में मीना कुमारी की जगह उनकी बॉडी डबल का उपयोग हुआ। इन दृश्यों में या तो कपड़े से छिपा चेहरा दिखाया गया, या लॉन्ग शॉट से काम चलाया गया, या फिर सिर्फ चेहरे के क्लोजअप शॉट्स ही मीना कुमारी पर फिल्माए गये। ऐसे दृश्यों में पद्मा खन्ना नामक अभिनेत्री उनकी बॉडी डबल बनीं, जिन्होंने'पाकीजा' के रिलीज होने के अगले साल अमिताभ बच्चन संग'सौदागर' (1973) में नायिका की भूमिका निभायी।बॉडी डबल के इस उपयोग के बावजूद'पाकीजा' के तकरीबन सारे ही गीतों और मुख्य दृश्यों में मीना कुमारी मौजूद रहीं। आखिरकार, इस फिल्म में किए गए अभिनय को उनके श्रेष्ठतम कामों में ऐसे ही नहीं गिना जाता। सिवाय एक गीत के, जिसमें वे होकर भी नहीं थीं।'चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो' नामक गीत मीना के राज कुमार के सीने से लगकर रोने के बाद शुरू होता है और साढ़े तीन मिनट लंबे इस कालजयी गीत के दौरान जहां मीना कुमारी नायक की बांहों में लिपटी रहती हैं, वहीं नाव में बैठकर नदी पार करते हुए राज कुमार उन्हें चांद के पार ले जाने की कसमें खाते हैं। यह पूरा गीत मीना कुमारी की बॉडी डबल पर शूट हुआ था और एक क्षण के लिए भी इस गीत में मीना का चेहरा नजर नहीं आता है।फिल्म में गीत से ठीक पहले आने वाला इमोशनल सीन तब शूट हुआ था जब मीना कुमारी का स्वास्थ्य बेहतर था, इसलिए इसमें मीना भावपूर्ण अभिनय कर रही हैं। लेकिन, इस सीन से लगे हुए गीत का फिल्मांकन लंबे अरसे बाद होना तय हुआ और उस दौरान मीना कुमारी का स्वास्थ्य इतना ज्यादा खराब हो गया कि सिर्फ चेहरे का क्लोजअप भर शूट करने के लिए भी वे सेट पर नहीं जा पायीं।

'चांद के पार चलो' फिर भी अमर हुआ और मीना कुमारी का ही गीत कहलाया। यह कमाल कमाल अमरोही की वजह से मुमकिन हुआ, जिन्होंने अलग होने के बाद भी मीना कुमारी को इतना चाहा कि उन्हें'पाकीजा' नाम का ताजमहल तोहफे में दिया।'चांद के पार चलो' का एक वर्जन फिल्म के बाकी गीतों के मिजाज का भी रिकार्ड हुआ था। ड्यूट न होकर सिर्फ लता मंगेशकर की आवाज में कुछ इस सेमी-क्लासिकल अंदाज में, कि मीना उस पर भी'पाकीजा' के दूसरे नृत्य-गीतों की तरह बेमिसाल नृत्य कर सकें। लेकिन उनकी शराबनोशी और बीमारी ने यह होने नहीं दिया और यह वर्जन सिर्फ याद बनकर रह गया।

मीना गंभीर बीमारी की चपेट में आ गयीं। शूटिंग रुक-रुककर होने लगी और शारीरिक थकान देने वाले कई गीतों में मीना कुमारी की जगह उनकी बॉडी डबल का उपयोग हुआ। इन दृश्यों में या तो कपड़े से छिपा चेहरा दिखाया गया, या लॉन्ग शॉट से काम चलाया गया, या फिर सिर्फ चेहरे के क्लोजअप शॉट्स ही मीना कुमारी पर फिल्माए गये। ऐसे दृश्यों में पद्मा खन्ना नामक अभिनेत्री उनकी बॉडी डबल बनीं, जिन्होंने'पाकीजा' के रिलीज होने के अगले साल अमिताभ बच्चन संग'सौदागर' (1973) में नायिका की भूमिका निभायी।

'चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो' नामक गीत मीना के राज कुमार के सीने से लगकर रोने के बाद शुरू होता है और साढ़े तीन मिनट लंबे इस कालजयी गीत के दौरान जहां मीना कुमारी नायक की बांहों में लिपटी रहती हैं, वहीं नाव में बैठकर नदी पार करते हुए राज कुमार उन्हें चांद के पार ले जाने की कसमें खाते हैं। यह पूरा गीत मीना कुमारी की बॉडी डबल पर शूट हुआ था और एक क्षण के लिए भी इस गीत में मीना का चेहरा नजर नहीं आता है।

श्रीदेवी संवेदनशील और खामोश अभिनेत्री

अपने जमाने में हिंदी सिनेमा के शौकिनों की सबसे पसंदीदा अभिनेत्री श्रीदेवी के साथ 'इंग्लिश विंग्लिश' में काम कर चुके आदिल हुसैन के लिए वे कई मायनों में खास थीं। आदिल हुसैन ने श्रीदेवी पर अपना यह संस्मरण हिंदी युग्म और वेस्टलैंड प्रकाशन से प्रकाशित किताब 'श्रीदेवी रूप की रानी' के एक हिस्से में लिखा था। जबकि श्रीदेवी के फिल्मी करियर की कहानी कहने वाली इस किताब को ललिता अय्यर ने लिखा है। हम आदिल के संस्मरण को पाठकों के लिए सामने ला रहे हैं।

जन्मदिन
13 अगस्त

मुझे याद है कि मैंने 1983 में 'सदमा' देखी थी। सिनेमा हॉल से मैं बेहद दुखी होकर निकला था। मेरा गला सूख रहा था और घर पहुंचने के बाद दो दिनों तक खाना खाने या किसी से बात करने का मन ही नहीं किया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक फिल्म किसी इंसान पर इस तरह का असर भी छोड़ सकती है। मैं तब सिर्फ बीस साल का था। उस वक्त तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि एक दिन मैं श्रीदेवी के साथ काम करूंगा।

मुझे श्रीदेवी की आंखों ने सबसे ज्यादा प्रभावित किया। यूं लगता था कि जैसे उनकी आंखें उनकी रूह में झांकने की खिड़कियां हैं। उनकी आंखें एकदम पारदर्शी-सी थीं और फिर भी उनमें दर्शकों की खातिर बेबाक भावनाओं को बेहद उम्दा और 'इंसानी' भावनाओं में तब्दील कर देने का हुनर था। मैं उन्हें देखकर हैरत में था। जब मैं उनसे पहली बार मिला तो बस इतना ही कह पाया, 'सदमा देखने के बाद मुझसे दो दिनों तक खाया नहीं गया।' श्रीदेवी ने मेरी ओर देखा और अचानक उनकी आंखें भर आईं। मुझे पूरा यकीन है कि मेरी इस स्वीकारोक्ति में उन्हें मेरी ईमानदारी दिखाई दे गई थी। श्रीदेवी हल्के से मुस्कुराईं और कहा, 'थैंक यू।' और हमने 'इंग्लिश विंग्लिश' की रिहर्सल शुरू कर दी। अगले घंटे, दिन, हफ्ते, महीने... जो मैंने उनके आस-पास रहते हुए गुजारे, उस दौरान मुझे समझ में आ गया कि मैं अभी तक जितने एक्टरों से मिल चुका हूं, श्रीदेवी उनमें सबसे संवेदनशील और सबसे खामोश एक्टर हैं जिन्होंने एक उम्दा कलाकार के स्तर तक खुद को लाने के लिए बहुत कड़ी मेहनत की है। मुझे लगता है कि वे यह बात समझती थीं कि भारतीय दर्शकों से भारतीय तरीके में ही संवाद करना होगा। हमारी प्राचीन और पारंपरिक नाट्यशैलियों, खासकर कुड़ियट्टम और कथकली में कलाकार आपस में भी बात कर रहे हों तब भी हमेशा दर्शकों से ही रूबरू रहते हैं। वे दर्शकों का पूरा सम्मान करते हैं और उनका उद्देश्य दर्शकों को एक उदात्त सत्य तक ले जाना होता है। किसी भी पारंपरिक भारतीय शैली का यही मूल उद्देश्य है- दर्शकों को सूक्ष्म से उदात्त की ओर ले जाना।

हालांकि बहुत सारे आधुनिक भारतीय कलाकार, चाहे वे ड्रामा स्कूलों में प्रशिक्षित हुए हों या नहीं, अभिनय की पाश्चात्य शैली से ज्यादा प्रभावित रहे हैं, जहां माना जाता है कि कलाकार और दर्शक के बीच में हमेशा एक चौथी दीवार बनी रहती है। इसके जरिए दर्शक अभिनेता के जीवन में चुपके से झांक सकते हैं। इसलिए कुछ हद तक ये मान बैठना कि सामने दर्शक हैं ही नहीं, कतई सच नहीं हो सकता। अगर पूरी तरह झूठ न भी हों तो ये आधा सच तो जरूर है कि सिनेमा के दर्शक हमारे सामने कहीं नहीं हैं। कारण तो मुझे ठीक-ठीक नहीं मालूम, लेकिन हो सकता है हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य में उनके प्रशिक्षण की वजह से हमेशा ऐसा लगता था कि श्रीदेवी का अपने दर्शकों के साथ एक किस्म का पवित्र रिश्ता है। इसलिए श्रीदेवी हमेशा दर्शकों के लिए अभिनय किया करती थीं। इसलिए नहीं कि उन्हें कोई दिखावा करना था, बल्कि इसलिए क्योंकि स्क्रिप्ट की गहरी सच्चाई को बरकरार रखते हुए वे अपने अलग-अलग किरदारों में अपनी जान डाल दिया करती थीं। श्रीदेवी अपने तरह की खास अभिनेत्री थीं। कैमरे के लिए अभिनय करते हुए भी उनकी एक्टिंग कभी-भी नकली नहीं लगी।

दूसरी ओर ऐसे कई भारतीय एक्टर हैं जो कैमरे के लिए अभिनय करते हैं, लेकिन उस लम्हे या उस स्थिति की सच्चाई के बगैर। और, इसलिए उनकी एक्टिंग हम पर गहरा असर नहीं डाल पाती। श्रीदेवी की 'कॉमिंग टाइमिंग' के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है। संदर्भ हल्का-फुल्का या संजीदा हो सकता है। लेकिन, एक सीन या अपने सह-अभिनेता की एक्टिंग से तारतम्य बिठाते हुए एक्टिंग में अपनी प्रतिक्रिया देना एक एक्टर के तौर पर हर सीन में उनके अतिसंवेदनशील और जागरूक बने रहने का नतीजा है। मुझे लगता है कि श्रीदेवी की चुप्पी का अभ्यास (इस बारे में कई लोगों ने बात की है कि कैसे श्रीदेवी फिल्म सेट पर खामोश रहती थीं)। दरअसल, उनकी 'परफेक्ट टाइमिंग' का कारण था। मुझे लगता है कि सेट पर खामोश रहकर वे अपनी ऊर्जा जाया होने से बचाती रहती थीं। यह शांत चुप्पी उनकी गहरी संवेदनशीलता और मयार्दा का कारण भी थी। मैं देख रहा हूं कि आजकल के एक्टरों में इस शिष्टता, मयार्दा या संवेदनशीलता की उस गहराई की सख्त कमी है जो श्रीदेवी में हुआ करती थी। विशुद्ध भारतीय स्टाइल में एक्टिंग करने वालीं श्रीदेवी एक खास एक्टर थीं। काश वे आज जिंदा होतीं। काश उनका हुनर और लोगों में भी होता। काश 'इंग्लिश विंग्लिश 2' बनाई जा सकती।

जेट न्यूज

समाचार विश्लेषण का हिंदी मासिक

रिलॉन्चिंग के बाद नये तेवर व कलेवर में

हर अंक होगा खास और संकलित करने वाला

EDUIndia
OUR EXPERTISE, YOUR PROSPERITY

Serving since 12 years.

info@eduindia.net.in
www.eduindia.net.in
7449812345 / 7449417777

ADMISSION GUIDANCE 2020-21

Direct Confirm Admission Guidance For

MBBS, BDS, MD/MS
B.Tech, M.Tech

SPECIAL GUIDANCE FOR NEET COUNSELLING

In Kolkata, Maharashtra, Karnataka, Tamil Nadu, Rajasthan and ABROAD

B.Tech (All) in top colleges of INDIA

BBA, MBA,GNM, B.Sc NURSING, B.PHARMA, B.Sc CARDIOLOGY, B.Sc. FORENSIC, CORPORATE LAW, HOTEL MANAGEMENT

100% PLACEMENT GUARANTEED IN TOP COMPANIES

We ensure your admission in lowest package.

JAYDEEP BHATTACHARYA
(Founder of EDU INDIA)